

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 1 • अंक: 15 • कठुआ, शनिवार 6 सितम्बर 2025 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में आपदा, भूस्खलन-बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त और फसलें तबाह

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : उत्तरी राज्यों में गुरुवार को लगातार और मूसलाधार बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश मानसून की शुरुआत से ही प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली प्रभावित हुई है।

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए हैं, सामान्य जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कारोबार ठप्प हो गया है।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार को भूस्खलन के बाद दो मकान ढह गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य मलबे में दब गए।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम ने एक महिला सहित तीन लोगों को बचाया और एक शव बरामद किया। कुल्लू के उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि पिछले



जम्मू



पंजाब



हिमाचल



दिल्ली

तीन-चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और तीन लोगों को बचा लिया गया है, एक शव बरामद किया गया है, जबकि अखाड़ा बाजार में मकान के मलबे में दबे छह लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि

बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, राज्य में कुल 1,292 सड़कें बंद हैं। इनमें से 294 सड़कें मंडी में, 226 कुल्लू में, 216 शिमला में, 204 चंबा में और 91 सिरमौर जिले में अवरुद्ध

हैं। स्थानीय मौसम कार्यालय ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है।

हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून के आगमन के बाद से राज्य में 95 बार अचानक बाढ़, 45 बार बादल फटने और 127 बड़ी भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं।

मानसून शुरू होने के बाद से वर्षाजनित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 343 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 43 लोग लापता हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में अब तक राज्य को 3,690 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों से कट गई है, क्योंकि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सभी सतही संपर्क गुरुवार को कई भूस्खलनों और बारिश के कारण सड़क के कुछ हिस्सों के बह जाने के कारण यातायात के लिए बंद कर दिए गए।

26 अगस्त से राजमार्गों और अन्य अंतर-क्षेत्रीय

■ शेष पेज 2...

एलजी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लिए मोदी और सीतारमण का आभार व्यक्त किया

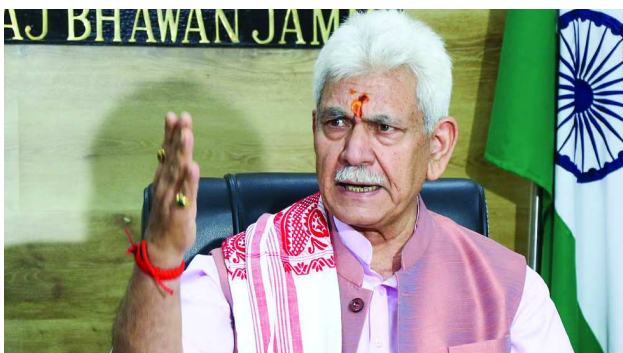
यह जम्मू-कश्मीर के लिए पहली बार है और केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद पद्धति अपनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है : सिन्हा

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।

एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला



सीतारमण जी का हार्दिक धन्यवाद। इससे एमएसएमई और किसान सशक्त होंगे और विनिर्माण

में तेजी आएगी। इससे जीवन और व्यापार में आसानी बढ़ेगी

■ शेष पेज 2...

केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्र ने अपने कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है, गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में अन्य बातों के अलावा, "एकीकृत पेंशन योजना के तहत नामांकन और सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या वीआरएस से तीन महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा" शामिल होगी।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ये नियम एनपीएस के तहत यूपीएस को एक

विकल्प के रूप में चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित सेवा मामलों को विनियमित करने के लिए हैं।

नियमों में कर्मचारी और सरकार द्वारा अंशदान, पंजीकरण में देरी और एनपीएस खाते में अंशदान जमा होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले मुआवजे और सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियमों या यूपीएस विनियमों के तहत लाभ के विकल्प को भी शामिल किया गया है।

सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, समय से पूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेदन, अमान्यता पर सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र तथा अन्य के अलावा

■ शेष पेज 2...

जम्मू प्रशासन ने तवी नदी में बाढ़ के बाद बहाली कार्य तेज किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : प्रशासन ने तवी नदी में आई बाढ़ के बाद जम्मू शहर के निचले इलाकों में बहाली कार्य और मलबा हटाने का काम तेज कर दिया है तथा प्रभावित क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति काफी हद तक बहाल कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने 70 प्रतिशत जलापूर्ति

और 80 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है।

रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण दहशत फैल गई, क्योंकि सूर्य पुत्री के नाम से प्रसिद्ध तवी नदी में 26 अगस्त को बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया, जिससे सैकड़ों घर और कई हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई, इमारतें और पशुधन बह गए, तथा जम्मू शहर, विशेषकर गुज्जर नगर और

पीरखो में हजारों लोग विस्थापित हो गए।

संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने कहा, झलाकों से कीचड़ और मलबा हटाने और तवी नदी के बाढ़ के पानी से जमा हुए मलबे को पूरी तरह से साफ करने के लिए सफाई अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रशासन इस मुद्दे पर पूरी तरह से काम कर रहा है।

कुमार ने उपायुक्त राकेश मिन्हास और जेएमसी आयुक्त देवांश यादव के साथ गुरुवार को मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद मजदूरों और मशीनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी की।

उन्होंने कहा, झलाकों की जल्द से जल्द सफाई सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या

■ शेष पेज 2...

11 साल बर्बाद हुए, झेलम नदी की सफाई से इसे रोका जा सकता था : उमर

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को 2014 की बाढ़ के बाद जम्मू एवं कश्मीर में शासन चलाने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया कि घाटी में बाढ़ दोबारा न आए।

अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 11 साल बर्बाद हो गए और उन्होंने कहा कि यदि झेलम नदी और उसके बाढ़ चौनल की सफाई की गई होती तो स्थिति अलग होती। शहर के बाढ़ प्रभावित

■ शेष पेज 2...

हिमाचल, पंजाब

सड़कों के बंद होने के कारण कठुआ से कश्मीर तक विभिन्न स्थानों पर 3,500 से अधिक वाहन फंस गए हैं। कुछ फंसे हुए वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के लिए सोमवार को राजमार्ग को आंशिक रूप से खोल दिया गया।

इसके अलावा, भूस्खलन और सड़कों के कुछ हिस्सों के बह जाने के कारण जम्मू-राजौरी-पुंछ राजमार्ग और बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ राजमार्ग सहित महत्वपूर्ण राजमार्ग यातायात के लिए बंद हैं।

26 अगस्त को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद पठानकोट-जम्मू खंड में कई स्थानों पर रेल लाइन के गलत संरेखण और टूटने के कारण जम्मू रेलवे डिवीजन में पिछले नौ दिनों से रेल यातायात स्थगित है।

26 अगस्त से जम्मू क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के कारण रेल और सड़क यातायात बुरी तरह बाधित होने से बढ़ी संख्या में लोग, विशेषकर तीर्थयात्री फंस गए हैं।

कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के निकट भूस्खलन से 34 लोगों की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर गुरुवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच 207.46 मीटर पर स्थिर रहा।

उन्होंने बताया कि जलस्तर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है, हालांकि बाढ़ का पानी अब भी आसपास के इलाकों और राहत शिवि. रों में भरा हुआ है।

दिल्ली सचिवालय के पास बाढ़ का पानी पहुँच गया है, जहाँ मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और प्रमुख नौकरशाहों के कार्यालय स्थित हैं। कश्मीरी गेट के पास श्री मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर तक भी बाढ़ का पानी पहुँच गया है।

एक भक्त ने कहा, ष्हर साल, जब यमुना का जल स्तर बढ़ता है, तो भगवान हनुमान की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। यह पवित्र जल है। हम इसका सम्मान करते हैं।

दिल्लीवासियों के लिए यह दोहरी मार थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव हो गया था और यमुना में बाढ़ आने से यातायात में भारी दिक्कतें आईं।

राजस्व विभाग के अनुसार, 8,018 लोगों को टेंटों में ले जाया गया है, जबकि 2,030 लोगों को 13 स्थायी आश्रयों में स्थानांतरित किया गया है।

पंजाब इस समय दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। यह बाढ़ सतलुज, व्यास और रावी नदियों के उफान के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मौसमी नालों के उफान का नतीजा है।

अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.75 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लगी फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई हैं।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब के अमृतसर और गुरदासपुर जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित किसानों सहित

लोगों से बातचीत की।

पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 7 सितंबर तक बंद रखने की बुधवार को घोषणा की।

हरियाणा में, राज्य के जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बुधवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें अधिका. रियों को राज्य भर में तत्काल जल निकासी और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

एलजी ने अगली ...

और साथ ही हमारी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अखनूर के लिए 35 आयुर्वेद पीजी सीटें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव का हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा

भारकारी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अखनूर के लिए 35 आयुर्वेद पीजी सीटें स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव जी का हार्दिक आभार। यह जम्मू-कश्मीर के लिए पहली बार है और केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद पद्धति अपनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है।

आयुर्वेद, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली ने वैश्विक लोकप्रियता हासिल कर ली है और दुनिया भर में लोग अपनी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं, शरीर, मन और आत्मा के कल्याण और विभिन्न रोगा. के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद तकनीकों को अपना रहे हैं।

जीएएमसी अखनूर में 35 सीटों वाले 7 नए पीजी डिग्री प्रोग्राम जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करेंगे और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाएंगे। आयुर्वेद पद्धतियों और अनुसंधान में मानव संसाधन और सहयोग निवारक और समग्र देखभाल को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

केंद्र ने एकी.त...

अनिवार्य सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/सेवा से निष्कासन का प्रभाव भी नए अधिसूचित नियमों के अंतर्गत शामिल हैं।

अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने अधिसूचना का स्वागत करते हुए कहा कि 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान निःसंदेह कर्मचारी कल्याण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा, णई योजना के लागू होने के बाद से यूपीएस में यह एक बहुत जरूरी संशोधन था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले वर्ष 24 अगस्त को यूपीएस शुरू करने को मंजूरी दी थी।

तदनुसार, वित्तीय सेवा विभाग ने इस वर्ष 24 जनवरी को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प/योजना के रूप में यूपीएस को अधिसूचित किया था। यूपीएस के संचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 है।

इसके बाद, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 19

मार्च, 2025 को पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के अंतर्गत शामिल होने का एक बार का विकल्प दिया गया है।

जम्मू प्रशासन ने ...

में मजदूर और छह जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। अधिकारी इस प्रक्रिया पर नज़र रख रहे हैं।

26 अगस्त की सुबह, शांत नदी एक प्रचंड बाढ़ में बदल गई, जिससे निचले इलाके, खासकर पीरखो, गुज्जर नगर, गोरखा नगर, राजीव नगर और अन्य नदी किनारे की कॉलोनियाँ, जलमग्न हो गईं। सड़कें जलमार्ग बन गईं, जिससे शमंदिरों के शहरश में दहशत के बीच बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू हो गए।

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक, पीरखो, आधे दबे वाहना. , मलबे, पत्थरों और उखड़े हुए पेड़ों से अटा पड़ा था। 300 से ज्यादा लोगों को, जिनमें अपनी माँओं से लिपटे बच्चे और चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्ग भी शामिल थे, बेतहाशा बचाव प्रयासों के ज़रिए बाहर निकाला गया। लेकिन डर अभी भी छाया की तरह छाया हुआ था।

कुमार ने कहा कि प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा, षपायुक्त, नगर आयुक्त और जेपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक – सभी जमीनी स्तर पर मौजूद हैं और जरूरी चीजों को बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इलाके में मलबा और गंदगी हटाने का काम चल रहा है।

संभागीय आयुक्त ने आगे कहा कि पानी और बिजली की सुविधाएं पूरी तरह बहाल की जा रही हैं।

उन्होंने कहा, षगभग 70 प्रतिशत जलापूर्ति बहाल कर दी गई है और शेष का काम तेजी से किया जा रहा है। क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।

जहां तक राहत का सवाल है, उन्होंने कहा कि इसका आकलन उपायुक्त द्वारा किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, षक बार यह काम पूरा हो जाए, तो प्रभावित परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि वह इस कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी है।

उन्होंने आगे कहा कि सभी बाढ़ प्रभावितों को पूरी राहत दी जाएगी तथा सभी सुविधाएं और आवश्यक आपूर्तियां शीघ्र ही बहाल कर दी जाएंगी।

जल आपूर्ति बहाली के लिए उपायुक्त ने सभी प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी जल टैंकर खरीदे हैं।

कुमार ने कहा, षसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हम सुविधा को पूरी तरह बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

11 साल बर्बाद ...

लासजान इलाके का दौरा करने के बाद अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, षमें यह सवाल पूछना होगा कि 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के बाद क्या किया गया था। जो लोग यहाँ शासन कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाढ़ दोबारा न आए।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बाढ़ प्रभावित हिस्सों के शुक्रवार रात तक बहाल होने की संभावना: जितेंद्र सिंह

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा की और कहा कि शुक्रवार देर रात तक राजमार्ग के बहाल होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर-रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर 2,000 से अधिक वाहन फंस गए।

उन्होंने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र 270 किलोमीटर लंबा यह मार्ग मंगलवार को भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद उधमपुर में जखेनी और चेनानी के बीच कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया। सिंह ने 11 दिसंबर को कहा, षधमपुर की उपायुक्त सलानी राय और एनएचआई तथा केंद्रीय अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थरद और बाली नाला में राष्ट्रीय राजमार्ग के बाढ़ प्रभावित हिस्सों का दौरा किया।

सिंह, जिनके साथ डीआईजी भी थे, ने आगे कहा, ष्कार्य चौबीसों घंटे चल रहा है, और श्रीनगर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आज देर रात तक बहाल हो जाने की संभावना है। एक यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा, षराजमार्ग चौथे दिन भी बंद है।

एनडीए ने रामगढ़ में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शिक्षा भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के एमवाई भारत से संबद्ध राष्ट्र विकास संघ (एनडीए) ने माननीय विधायक रामगढ़ और पूर्व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जम्मू-कश्मीर, डॉ. देविंदर कुमार मन्थाल के मार्गदर्शन में रामगढ़ में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में डीडीसी सदस्य रामगढ़, श्रीमती अंतिया चौधरी, सहायक कमांडेंट सुरेश कुमार (तनोट वारियर्स, 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल) और सहायक कमांडेंट बीएसएफ अखिलेश कुमार की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनडीए के मुख्य पदा. धिकारी श्री सुशील सिंह चरक ने की, जिन्होंने अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व पर जोर दिया, साथ ही मेजर ध्यानचंद – ष्छोंकी के जादूगर को श्रद्धांजलि भी दी।



समारोह का मुख्य आकर्षण तनोट वारियर्स, 13वीं बटालियन बीएसएफ और विलेज नंगा स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वित. रित करना था, जिसमें क्षेत्र में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए उनकी उत्कृ ष्ट भागीदारी और प्रतिबद्धता को मान्यता दी गई।

विशेष अतिथियों में श्री प्रेम पॉल चौधरी (पूर्व सरपंच), श्री अनिल गुप्ता (पूर्व उपाध्यक्ष, नगर समिति रामगढ़), सुश्री नैसी चौधरी (अध्यक्ष

रामगढ़), श्री संदीप गुप्ता, श्री तिलक, श्री अमरीक सिंह और श्री गुरदेल शामिल थे, जिनकी उपस्थिति ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने तनोट वारियर्स, 13वीं बटालियन बीएसएफ को उनके रसद और स्थानीय सहयोग के लिए तथा सो. रिसो पिज्जा एंड मील मस्तिद्यां, रामगढ़ के प्रबंध निदेशक श्री गुरदयाल राणा को कार्यक्रम की सफलता में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

किश्तों में संविधान बदलने का खेल



राजेंद्र शर्मा

संसद के मानसून सत्र की अपेक्षाकृत छोटी अवधि के दौरान ही, अनेक राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार, जहां देश के मूड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वहीं इसी दौरान देश को दो बड़े सरप्राइज भी देखने को मिले हैं। देश के मूड में बदलाव का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संसद के इस सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री के संसद पहुंचने पर, सत्तापक्ष के सांसदों की तरफ से ही सही, उनका जोशीले नारों के साथ स्वागत किए जाने से हुई थी और प्रधानमंत्री ने भी कम से कम लोकसभा को, आपरेशन सिंदूर पर हुई विस्तृत चर्चा के अपने अति-विस्तृत उत्तर का सम्मान दिया था, जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के राज के ग्यारह साल में दुर्लभ ही होता गया है। उसी सत्र का अंत विपक्षी सांसदों द्वारा ही सही, प्रधानमंत्री को संबोधित कर "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाए जाने के साथ हुआ। और बिहार में जन-विस्फोट की एसआइआर प्रक्रिया पर, संसद में बहस कराने विशेष संदर्भ में लगे, इन नारों के लगाए जाने से बड़ी खासियत, विपक्ष के इन नारों पर सत्ताधारी पार्टी के सांसदों की जैसे हथियार ही डाल देने की प्रतिक्रिया थी। सामान्यतः जो होता आया है, उसके विपरीत, सत्ताधारी सांसदों की ओर से विपक्ष के नारों को अपने कंठबल से दबाने का, शायद ही कोई वास्तविक प्रयास किया जा रहा था।

और जहां तक इसी सत्र के दौरान हुई दो बड़ी हैरान करने वाली घटनाओं का सवाल है, पहली घटना जो सत्र के शुरू में ही हुई, राज्यसभा के सभापति तथा उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफा देने की ही रही। यह घटना इस कदर अचानक हुई कि उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के महीने भर बाद भी, जबकि उनकी जगह लेने के लिए नये उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सत्तापक्ष और एकजुट विपक्ष, दोनों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर-शोर से चल पड़ा है, अब तक प्रेक्षकों द्वारा इस पर हैरानी ही जतायी जा रही है कि उपराष्ट्रपति को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा। बेशक, इस संबंध में पहले दिन से ही तरह-तरह की अटकलें लगायी जा रही हैं और बहुत सी अटकलें निराधार भी नहीं हैं। कम से कम इतना तो साफ ही है कि वर्तमान सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीशों की धनखड़ से नाराजगी इस त्यागपत्र प्रकरण के पीछे थी। फिर भी इस प्रकरण के पीछे एक रहस्यकथा तो अब भी बनी ही हुई है। और इस रहस्यकथा को इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ के सार्वजनिक परिदृश्य से पूरी तरह से अदृश्य ही हो जाने ने और भी गाढ़ा रंग दे दिया है।

दूसरा हैरान करने वाला प्रकरण, सत्र के ऐन आखिर में सामने आया। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की सारी प्रक्रिया को धता बता हुए और विपक्ष ही नहीं, सत्तापक्ष को भी हैरान करते हुए, लोकसभा में अचानक 130वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश कर दिया गया। यह प्रस्ताव संविधान में संक्षेप में इस आशय के संशोधन का है कि पांच साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध के आरोपी, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय या राज्य मंत्री तक को, अगर बिना जमानत के एक महीना कैद में गुजारना पड़े तो, एक महीना पूरा होते ही उसका उक्त पद खुद-ब-खुद छिन जाएगा। इस संविधान संशोधन प्रस्ताव को विपक्ष के कड़े विरोध के बाद भी लोकसभा में पेश किया गया और उसके तुरंत बाद ही संयुक्त संसदीय समिति द्वारा छानबीन के लिए भेज दिया गया। इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति का गठन खुद विवादों के घेरे में आता जा रहा है, क्योंकि एक-एक कर विपक्षी पार्टियों के प्रस्तावित समिति से दूर रहने का एलान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है।

जैसाकि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता था, सत्ताधारी भाजपा और किसी हद तक उसका गठबंधन भी, इस संशोधन को राजनीति में "शुचिता" लाने की अपनी कोशिश के रूप में पेश करना चाहता है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में इस संशोधन प्रस्ताव को पेश करते हुए दी गयी दलीलों से यह कोशिश पूरी तरह से स्पष्ट थी। इसके बाद यदि अगर कोई कसर रह गयी थी, तो वह मानसून सत्र के फौरन बाद, बिहार, बंगाल तथा अन्य राज्यों के प्रधानमंत्री के चुनावी तथा चुनाव-पूर्व दौरे पर दिए गए भाषणों से साफ हो गयी। इन भाषणों में प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के उक्त संविधान संशोधन के विरोध को, उनके नेताओं के भ्रष्ट होने और भ्रष्टाचारियों को बचाने का सबूत बनाकर



संसद के छोटे मानसून सत्र में देश के मूड और राजनीति में बड़ा बदलाव देखा गया। सत्र की शुरुआत पीएम मोदी के स्वागत से हुई, जबकि अंत विपक्ष के "वोट चोर, गद्दी छोड़" नारों से।

इसी दौरान दो बड़े घटनाक्रम हुए कृपहला, उपराष्ट्रपति धनखड़ का अचानक इस्तीफा और सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाना; दूसरा, लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश होना, जिसके तहत गंभीर आरोपों में जेल गए नेताओं की कुर्सी स्वतः खत्म हो जाएगी। विपक्ष का मानना है कि यह संशोधन विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने और संवैधानिक मूल्यों से छेड़छाड़ की साजिश है।

पेश करने की कोशिश की। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर अपना पुराना दावा दोहराया कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है।

कहने की जरूरत नहीं है कि उक्त संविधान संशोधन प्रस्ताव के पीछे मोदी सरकार की राजनीति में शुचिता लाने की चिंता होने के दावे को, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों के सिवा शायद ही किसी ने गंभीरता से लिया होगा। इस संशोधन प्रस्ताव के दायरे में प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल किए जाने के बावजूद, यह सचाई किसी से छुपी नहीं रही है कि ये पद सिर्फ दिखावे के लिए शामिल किए गए हैं; यह दिखाने के लिए कि यह कानून विपक्ष ही नहीं, सत्तापक्ष पर भी लागू होगा। लेकिन, यह दिखावा एक ऐसी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे उसके पक्के से पक्के समर्थक भी, सत्तापक्ष और विपक्ष में भेदभाव न करने का दिखावा तक करने की उम्मीद नहीं करते हैं, फिर आम लोगों के इस दिखावे पर विश्वास करने का तो सवाल ही कहां उठता है। उल्टे आम देशवासी किसी न किसी हद तक विपक्ष की इस दलील से प्रभावित है कि यह संविधान संशोधन, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने और अस्थिर करने के लिए लाया गया है। वास्तव में प्रधानमंत्री समेत खुद सत्ताधारी पार्टी द्वारा इस संविधान संशोधन विधेयक के बहाने से, विपक्ष को निशाना बनाए जाने की कोशिशों से, इस आशंका की पुष्टि ही हुई है।

"जेल से सरकार नहीं चल सकती" की सत्तापक्ष की दलीलों का इशारा भी, मोदी राज द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर रहते केजरीवाल को और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, सीआइडी और ईडी के बनाए मामलों में जेल में डाले जाने की ओर ही है। वास्तव में हेमंत सोरेन ने तो राजभवन से अपनी गिरफ्तारी से ऐन पहले इस्तीफा देकर और अपनी पार्टी का वैकल्पिक मुख्यमंत्री बनवा कर, झारखंड में विपक्षी सरकार को इस हथकंडे से गिराने की कोशिश को, विफल भी कर दिया था। केजरीवाल ने ही गिरफ्तारी के बाद और अंततः जमानत के बाद भी, इस्तीफा देने से इंकार कर दिया था और इस तरह, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार को हटाए जाने की कोशिश को विफल किया था। अब इस संशोधन के जरिए, इस हथकंडे के सहारे असुविधाजनक

विपक्षी सरकारों को हटाने का ही रास्ता तैयार किया जा रहा है। और इस हथकंडे का इस्तेमाल कोई अतिरंजित आशंका नहीं है। तमिलनाडु तथा केरल समेत, ऐसा कोई विपक्ष-शासित राज्य नहीं है, जहां ईडी-सीबीआई आदि केंद्रीय एजेंसियों ने, मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक के खिलाफ किसी न किसी प्रकार की जांच नहीं छेड़ रखी है। दिल्ली और झारखंड के मामले इसके गवाह हैं कि ऐसी जांचों को मुख्यमंत्रियों तक की हिरासत की मांग तक पहुंचने में और फिर उनकी जमानत की राह मुश्किल से मुश्किल बनाए जाने में, ज्यादा समय नहीं लगता है। यही वह प्रशासनिक संस्कृति है, जो मोदी राज के ग्यारह साल की पहचान ही बन गयी है।

वास्तव में इस संशोधन के बाद, इन केंद्रीय एजेंसियों को, केंद्रीय सत्ताधारी दल के पक्ष में दलबदल का हथियार बनाना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि मंत्री-मुख्यमंत्री सभी के सिर पर यह तलवार लटकती रहेगी कि महीने भर उन्हें जमानत न मिलना सुनिश्चित किए जाने भर की जरूरत है, उनका कैरियर आसानी से चौपट किया जा सकता है। सभी जानते हैं कि हिमंता बिश्वशर्मा से लेकर अजीत पवार तक, दर्जनों बड़े-बड़े विपक्षी नेताओं को इन्हीं एजेंसियों के ब्लैकमेल के जरिए, सत्तापक्ष के पाले में पहुंचाया गया है। प्रस्तावित संशोधन इन एजेंसियों को और घातक बना देंगे। याद रहे कि यह तलवार सिर्फ विपक्ष के ही सिर पर नहीं लटक रही होगी, सत्तापक्ष के अपने मंत्रियों से लेकर, उसके सहयोगियों के भी सिर पर लटक रही होगी। तेलुगू देशम तथा जनता दल यूनाइटेड में, इस संविधान संशोधन पर बेचौनी की खबरें, सिर्फ अटकलें ही नहीं हैं।

बेशक, ये तमाम आशंकाएं तब कुछ अपरिपक्व लग सकती हैं, जब हम इस बात को हिसाब में लेते हैं कि इस तरह के संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखने की शक्ति तो मोदी सरकार के पास है, लेकिन ऐसे किसी संशोधन को पारित कराने की शक्ति उसके पास नहीं है। तब तो बिल्कुल ही नहीं, जब पूरा विपक्ष प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है, जबकि खुद सत्ताधारी गठजोड़ इतना एकजुट नजर नहीं आता है। कम से कम फौरन सत्तापक्ष की यह मंशा पूरी होती नहीं लगती है और फौरन तो उसका मकसद, संसद में विपक्ष की ओर से उठायी गयी, बिहार में एसआइआर प्रक्रिया पर बहस की मांग से ध्यान बंटाना ही ज्यादा लगता है। यह दूसरी बात है कि इस पैतरे के बाद से, विपक्ष की "वोट बचाओ यात्रा" के माध्यम से, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा और भी बढ़ा हो गया है।

लेकिन, वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान बंटाने के साधन के रूप प्रस्तावित संविधान संशोधन के इस तात्कालिक उपयोग से अलग, संविधान के बुनियादी जनतांत्रिक सिद्धांतों तथा प्रावधानों से छेड़छाड़ करने वाले ऐसे संविधान संशोधनों के उछाले जाने का, एक और गहरा उद्देश्य भी है। यह एक के बाद एक, इस प्रकार के संशोधनों को उछालने के जरिए, संविधान को ही बदलने के लिए माहौल बनाना है। सत्ताधारी भाजपा और उसके प्रधानमंत्री दिखाने के लिए भले संविधान नहीं बदलने देने की कसमें खाते हैं, वास्तव में वे किस्तों में संविधान बदलने की ही कोशिश कर रहे हैं। एक देश, एक चुनाव के प्रस्ताव से संबंधित संविधान संशोधनों का निपटारा अभी हुआ भी नहीं है, तब तक एक और बड़े संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। और यह सब संविधान की प्रस्तावना में से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आदि को निकालने के लिए संशोधनों की, आए दिन उन्हीं की कतारों के बीच से उठती रहने वाली मांगों के ऊपर से है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और श्लोकलहरर के संपादक हैं।)

बाढ़ संकट से निपटने में एनसी सरकार पूरी तरह विफल - भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी ने तत्काल कार्रवाई की मांग की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू संभाग में हाल ही में आई बाढ़ की स्थिति ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार की अक्षमता, लाप. रवाही और तैयारी की कमी को उजागर कर दिया है। पिछले कई दिनों से जम्मू के लोग तवी नदी, चिनाब नदी और आसपास के इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। इन बाढ़ों से हुई तबाही व्यापक है - गाँव जलमग्न हो गए हैं, सड़कें बह गई हैं, घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कृषि भूमि बर्बाद हो गई है। फिर भी, सरकार मूकदर्शक बनी हुई है और समय पर राहत या पुनर्वास के उपाय करने में विफल रही है।

जम्मू संभाग में स्थिति बेहद चिंताजनक है। पिछले पाँच दिनों से, न पानी की आपूर्ति है, न बिजली, न सड़क संपर्क, और न ही फंसे हुए लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ। पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र निष्क्रिय बना हुआ है। ज़मीनी स्तर पर न शौचालय, न भोजन वितरण शि. विर, न चिकित्सा दल, और न ही पुनर्वास प्रक्रिया दिखाई दे रही है। यह सिर्फ़ प्रशास. निक विफलता नहीं, बल्कि आपराधिक लाप. रवाही है जहाँ आम नागरिकों की जान जोखिम में डाली गई है।

स्थिति को और भी बदतर बनाने वाली बात सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की पूरी तरह से चुप्पी है।

लोगों को बचाने, बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए युद्धस्तर पर काम करने के बजाय, सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ जम्मू संभाग के लोग जीवन-रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री और अधिकारी नींद में सो रहे हैं।

भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से सवाल किया है कि जब लगातार मौसम संबंधी



अलर्ट जारी किए जा रहे थे, तब एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए? तवी और चिनाब नदियों के बढ़ते जलस्तर से निपटने के लिए पहले से कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई? अगर केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए पहले ही धन मुहैया करा दिया है, तो वह धन ज़मीन पर क्यों नहीं दिख रहा? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का क्या हुआ, जिसे ऐसी विकट परिस्थितियों में काम करना था? सच तो यह है कि सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है - चाहे वह तैयारी हो, बचाव हो, राहत हो या पुनर्वास।

उमर अब्दुल्ला की तरह सिर्फ़ 10 करोड़ के पैकेज की घोषणा इस आपदा की गंभीरता को समझने के लिए काफी नहीं है। जब हज़ारों परिवार अपने घर, अपना सामान और अपनी रोज़ी-रोटी गँवा चुके हैं, तो 10 करोड़ क्या करेंगे? यह घोषणा सरकार की अक्षमता को छिपाने के लिए एक राजनीतिक हथकंडा है। लोगों को घोषणाओं की नहीं, ज़मीनी स्तर पर तुरंत राहत चाहिए।

उन्हें पानी, बिजली, खाना, आश्रय, चिकित्सा और पुनर्वास चाहिए।

भाजपा का दृढ़ विश्वास है कि इस गंभीर मानवीय संकट में सरकार को निर्णायक और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी माँग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बाढ़ प्रभावित

परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अपने सभी संसाधन लगा दे। हर प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएँ, अस्थायी आश्रय और शौचालय उपलब्ध कराए जाएँ, और बिना किसी देरी के उचित खाद्य वितरण शुरू किया जाए। सड़कें और संचार संपर्क प्राथमिकता के आधार पर बहाल किए जाएँ, और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास जल्द से जल्द शुरू किया जाए। जिन किसानों की फसलें और ज़मीनें नष्ट हुई हैं, उन्हें मुआवज़ा दिया जाए।

इसमें जवाबदेही होनी चाहिए ताकि आपदा राहत के लिए निर्धारित धनराशि का राजनी. तिक हितों के लिए दुरुपयोग न हो।

यही वह समय है जब सरकार को इस मुश्किल घड़ी में आगे आकर ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए। दुर्भाग्य से, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने एक बार फिर अपने लोगों को निराश किया है। भाजपा जम्मू संभाग के नागरिकों को आश्वस्त करती है कि इस कठिन घड़ी में हम उनके साथ हैं। हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार से कार्रवाई की माँग करेंगे और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। जम्मू के लोग बेहतर शासन, मज़बूत आपदा प्रबंधन और एक ऐसी सरकार के हकदार हैं जो संकट के समय उनके लिए काम करे - न कि ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों के कष्टों के दौरान सोती रहे।

इन बाढ़ों से हुई तबाही इस बात की याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर सरकार समय पर एहतियाती कदम उठाए और लोगों के साथ खड़ी रहे, तो उनके प्रभाव को कम ज़रूर किया जा सकता है। दुर्भाग्य से, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ऐसा करने में विफल रही है। भाजपा तब तक संघर्ष करती रहेगी जब तक जम्मू संभाग के प्रत्येक प्रभावित परिवार को उचित राहत, पुनर्वास और न्याय नहीं मिल जाता।

सबका जम्मू कश्मीर

गंदेरबल में तीन दिवसीय गंगबल यात्रा शुरू

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू एवं कश्मीर के गंदेरबल जिले में शनिवार को तीन दिवसीय वार्षिक गंगबल यात्रा बड़े धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुई।

उन्होंने बताया कि यात्रा को कश्मीर संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने मध्य कश्मीर जिले के नारानाग मंदिर से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर बोलते हुए गर्ग ने यात्रा के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की सराहना की।

श्रद्धेय छड़ी पूजा का आयोजन किया गया, जिसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के तीर्थयात्रियों का एक समूह यात्रा पर रवाना हुआ, जिसका आयोजन हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों, पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ श्रद्धालु पवित्र गंगबल झील तक 15 किलोमीटर की यात्रा पर निकले, जो हरमुख पर्वत श्रृंखला में लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कहा कि पवित्र अनुष्ठान गंगबल झील के तट पर किए जाएंगे और तीर्थयात्री अगले दिन वापस लौट आएंगे।

स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुंछ में तलाशी अभियान शुरू

सबका जम्मू कश्मीर

मैंडर/जम्मू : सुरक्षा बलों ने शनिवार को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सीमावर्ती 11 इलाकों में घेराबंदी और तलाशी अभियान (कासो) शुरू किया। यह ऑपरेशन मैंडर, मनकोट और सुरनकोट के बेहरा कुंड, पोथा जंगल, सुरनकोट, पीर तना. रा, सांगला, मोहल्ला लोहार चंडीमढ़, कंडी, कांगड़ा, केरी गलहुटा, मुगल मारा मोहल्ला मुरी और पोली वाला ढोक इलाकों में चलाए गए। अधिक. रियों के अनुसार, स्थानीय निवासियों द्वारा सुरक्षा एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधि के बारे में सूचित किए जाने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान विशेष अभियान समूह (एसआ. जी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा चलाया गया।

एमबीबीएस प्रवेश घोटाला मामले में कश्मीर अपराध शाखा ने छह स्थानों पर छापे मारे

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : कश्मीर में अपराध शाखा ने एमबीबीएस प्रवेश घोटाले के सिल. सिले में शनिवार को घाटी में छह स्थानों पर तलाशी ली।

अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामले पर कार्रवाई कर रही थी, जिन पर कथित तौर पर कई लोगों को बांग्लादेश में फर्जी एमबीबीएस प्रवेश की पेशकश करने का आरोप था।

अपराध शाखा के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में पता चला है कि इन व्यक्तियों द्वारा मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पर भारी मात्रा में धन एकत्र किया गया था, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज को कोई धन हस्तांतरित नहीं किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में धोखाधड़ी के आरोप पुष्ट हुए हैं, जिसके अनुसार धोखाधड़ी और आपरा. धिक षड्यंत्र से संबंधित मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत दंडनीय है।

आरोपियों की पहचान बिजबेहरा के पीरजादा आबिद और पुलवामा के करीमाबाद के सैयद वसीम के रूप में हुई है, जो दोनों वर्तमान में नटिपोरा के आजाद बस्ती में रह रहे हैं; कोकरनाग के ताकिया मगाम के निवासी सैयद सुहैल ऐजाज, जो वर्तमान में बेमिना में एनआर कॉलोनी के सामने मुस्लिमाबाद में रह रहे हैं, और बेमिना के निवासी जैगम खान।

प्रवक्ता ने बताया कि आबिद यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर नामक एक शैक्षिक कंसल्टेंसी का मालिक था, जबकि अन्य लोग ओवरसीज कंसल्टेंसी के मालिक थे।

बानी विधायक डॉ. रामेश्वर ने दुग्गनी में 38 वर्षा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की

सबका जम्मू कश्मीर

बानी : क्षेत्र में लगातार बारिश से हुई तबाही के बीच, बानी विधायक डॉ. रामेश्वर सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के दुग्गनी गाँव के बाढ़ और वर्षा प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उन्हें तत्काल राहत प्रदान की।

कुल 38 परिवारों को कठिन परिस्थिति से निपटने में मदद के लिए राशन किट, कंबल, टेंट और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्रदान की गईं।

डॉ. रामेश्वर सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता मरहूफ माली, परवीन सिंह, पुष्पिंदर सिंह और गणेश सिंह के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत अभियान का निरीक्षण किया। विधायक ने यह सुनिश्चित किया कि विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रय के लिए पास के सरकारी भवनों में भी स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई घर असुरक्षित हो गए थे।

मौके पर मौजूद लोगों से बात करते हुए, डॉ. सिंह ने कहा, मैं इस संकट की घड़ी में हर परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। प्रकृति के प्रकोप ने भारी कष्ट पहुँचाया है,



लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कोई भी भूखा न सोए और न ही ठंड में कष्ट सहे। मेरी प्राथमिकता उन लोगों को भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने अपना घर और सामान खो दिया है। उन्होंने प्रशासन से राहत और पुनर्वास कार्यों में निरंतर सहयोग की अपील की और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर जोर दिया।

डॉ. सिंह ने आगे कहा, मैं सरकार से पुनर्वास कार्यों में तेज़ी लाने और प्रभावित परिवारों को

पर्याप्त मुआवज़ा देने का आग्रह करता हूँ ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें।

स्थानीय निवासियों ने ऐसे कठिन समय में व्यक्तिगत रूप से पहुँचकर तत्काल आपूर्ति प्रदान करने के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर मिली सहायता से उन्हें राहत और आशा मिली है। दुग्गनी में राहत वितरण सामुदायिक भागीदारी और एकजुटता की भावना से चिह्नित था।

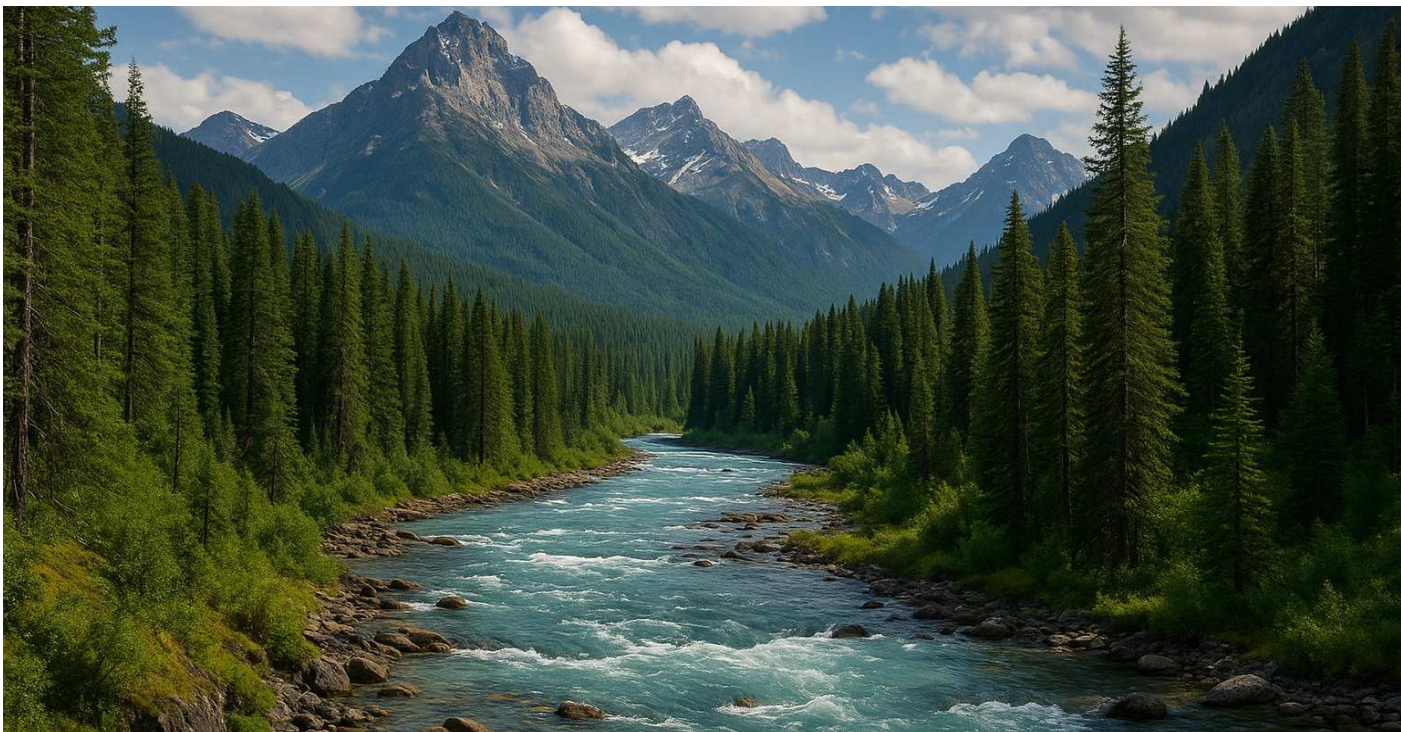
प्रकृति का संदेश : इंसानियत सबसे महान



आई.डी. खजुरिया

प्रकृति समय-समय पर अपने अद्भुत और भयावह स्वरूप से मानवजाति को यह समझाने की कोशिश करती है कि जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा और हवा जैसे तत्व उसके ही नियमों से चलते हैं। इन्हीं तत्वों से घास-पात से लेकर विशाल वृक्षों तक, छोटे जीव-जंतुओं से लेकर मानवजाति की तमाम नस्लों तक, हर प्रक्रिया संचालित होती है।

मानव चाहे किसी भी शक्ल-सूरत का हो, किसी भी धर्म या विचारधारा का प्रचार करता हो, या फिर एक-दूसरे को मिटाने का भ्रम पालता हो, अंततः वह प्रकृति के आगे असहाय है। हाल ही में बादल फटना, धरती का बह जाना और अचानक भारी बारिश का कहर इसका जीता-जागता उदाहरण है। चसौटी से लेकर लखनपुर तक, कठुआ के कुमरी कंठेरा से लेकर जम्मू स्मार्ट सिटी तक, उधमपुर की देवका से लेकर विजयपुर तक, पूरे पीर पंजाल से लेकर चिनाब वैली और पूरे कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल व उत्तराखंड तक कुहर जगह प्रकृति ने मानव का घमंड चकनाचूर कर दिया। चाहे वे उपग्रह विकसित करने वाले वैज्ञानिक हों या खुद को सबसे शक्तिशाली समझने वाले राष्ट्र, सभी को यह सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि इंसान प्रकृति से बड़ा नहीं। प्रकृति ने यह भी समझाया कि कोई नस्ल बड़ी



या छोटी नहीं, कोई धर्म या जाति श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं। हर प्राणी सांस लेता है तो जीता है, और प्रकृति की मर्जी से उसे भोजन और जल प्राप्त होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस धरती पर रहकर अपना योगदान दे, न कि विभाजन और विनाश फैलाए।

प्रकृति स्वयं "भिन्नता में एकता" का उदाहरण है। हर प्रक्रिया आपसी एकता और आपसी संघर्ष से जन्म लेती है। यही जीवन का चक्र है जिसमें नई प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं और पुरानी समाप्त हो जाती हैं। यही नियम ब्रह्मांड में भी लागू है, जहां संघर्ष और एकता की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मौसम और प्राकृतिक घटनाएं हमें यही संदेश देती हैं।

लेकिन मानवजाति ने जन्म लेते ही खुद को जाति, धर्म और फिरकों में बांट दिया है। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी इंसान एक-दूसरे की दुश्मनी निभाने से बाज नहीं आता। अब समय आ गया है कि इस दुश्मनी का अंत किया जाए और भिन्नता में एकता के सत्य को अपनाया जाए।

मानव निर्मित बार्डर सरल किए जाएं, ताकि पूरी मानवजाति स्वतंत्र रूप से हर जगह आ-जा सके। युद्धों का अंत हो और हथियार बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह बंद की जाए। परमाणु और न्यूक्लियर बमों को नष्ट कर दिया जाए। हर समस्या का समाधान युद्ध से नहीं, बल्कि बातचीत से निकाला जा सकता है।

हैक और निकास जाना चाहिए। आज दुनिया बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग,

खतरनाक बीमारियों, पीने के पानी की कमी, भोजन की किल्लत और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। यह सब बादल फटने जैसी घटनाओं से कम भयावह नहीं। ऐसा लगता है जैसे एक दुनिया अमीरों की है और दूसरी गरीबों की, जिन पर हर दिन बादल फटते हैं और पहाड़ खिसकते हैं।

अगर हर इंसान को रोजगार मिले, छत मिले, साफ पानी और हवा मिले तो धरती और भी सुंदर बन सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फिरकापरस्ती और धार्मिक आधार पर पैदा की गई दुश्मनी का अंत हो। इंसानियत सबसे महान है। गर्व से कहना चाहिए : हम सबसे पहले इंसान हैं।

हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान : सबसे पहले इंसान।

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा

चार दिनों के बाद फंसे वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुला

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को इसकी शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उधमपुर-रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद रहा।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुख्यमंत्री ने हाल ही में हुई लगातार बारिश से क्षतिग्रस्त हुए जम्मू-श्रीनगर एनएच-44 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

इसमें कहा गया है कि अब्दुल्ला ने अधिकारियों को सड़कों की शीघ्र बहाली, यातायात की सुचारु आवाजाही और विशेष रूप से घाटी और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पोस्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने तथा जनता की आवश्यकताओं पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने के लिए विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को शनिवार को केवल फंसे हुए वाहनों के लिए फिर से खोल दिया



गया। यह राजमार्ग इस सप्ताह के शुरू में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद उधमपुर जिले में कई भूस्खलनों और 60 मीटर हिस्से के धंसने के कारण चार दिनों तक बंद रहा था।

हालांकि, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली 250 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क पर सामान्य यातायात अभी तक बहाल नहीं हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के रामबन परियोजना निदेशक शुभम ने कहा कि सामान्य यातायात के लिए राजमार्ग को जल्द से जल्द खोलने के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ष्मने शुक्रवार शाम छह बजे तक मरम्मत का काम लगभग पूरा

कर लिया था और हमें उम्मीद थी कि आज (शनिवार) सुबह इस रणनीतिक राजमार्ग पर यातायात शुरू हो जाएगा। लेकिन रात भर हुई बारिश ने हमारे प्रयासों में बाधा डाली।

शुभम ने कहा कि चेनानी और उधमपुर के बीच बेनाली नाले में सड़क के 60 मीटर हिस्से के ध्वस्त हो जाने के कारण काम तुरंत पुनः शुरू कर दिया गया। चट्टानों के आधार को स्थिर होने के लिए कुछ समय देने के बाद, फंसे हुए वाहनों, विशेषकर फलों से लदे ट्रकों, तेल टैंकरों और हल्के मोटर वाहनों सहित नाशवान वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को दोनों ओर से विनियमित तरीके से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। अधिकारियों के अनुसार, 26

अगस्त को हुई बारिश के बाद राजमार्ग के दोनों छोर पर 2,000 से अधिक वाहन फंसे गए थे, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई और जम्मू क्षेत्र में मौत और विनाश का मंजर छा गया। उधमपुर में 27 अगस्त को सुबह 8.30 बजे समाप्त होने वाली 24 घंटे की अवधि के दौरान 630 मिमी की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो 31 जुलाई, 2019 को 342 मिमी की उच्चतम वर्षा से अधिक है, जबकि जम्मू में इसी अवधि के दौरान 380 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो 1910 में वेधशाला स्थापित होने के बाद से शहर में दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा है।

रामबन सेक्टर में विभिन्न स्थानों पर राजमार्ग के बाकी हिस्से से भूस्खलन का मलबा और पत्थर पहले ही साफ कर दिए गए हैं। मुख्य समस्या उधमपुर-चेनानी खंड की थी और 90 प्रतिशत काम लगभग पूरा हो चुका है।

एनएचएआई अधिकारी ने कहा, अगर मौसम ठीक रहा और कोई नुकसान नहीं हुआ तो हम फंसे हुए सभी वाहनों को निकालने के बाद रविवार को राजमार्ग को सामान्य यातायात के लिए खोल देंगे। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन मुगल रोड पर चल रहे हैं, जो जम्मू क्षेत्र के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ता है, तथा सिंथन टॉप रोड पर चल रहे हैं, जो जम्मू के किश्तवाड़ जिले को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से जोड़ता है।

जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी ने श्रीनगर में साइबर कानूनों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया



सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली (जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी के मुख्य संरक्षक) के संरक्षण में और शासी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के मार्गदर्शन में, जम्मू-कश्मीर न्यायिक अकादमी ने कश्मीर प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के न्यायिक अधिकारियों के लिए साइबर कानून और डिजिटल साक्ष्य की सराहना और संचालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह का संचालन न्यायिक अकादमी की निदेशक सोनिया गुप्ता ने किया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को साइबर कानूनों के उभरते और विकसित होते क्षेत्र तथा न्यायिक कार्यवाहियों में डिजिटल साक्ष्य के प्रभावी संचालन के बारे में अद्यतन ज्ञान और

व्यावहारिक अंतर्दृष्टि से लैस करना है।

तकनीकी सत्रों का नेतृत्व दिल्ली के प्रख्यात साइबर विशेषज्ञ डॉ. निशीथ दीक्षित ने किया, जिन्होंने डिजिटल युग में न्यायिक जागरूकता के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला, जहाँ साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मुकदमेबाजी को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने डिजिटल साक्ष्यों की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने वाले केस लॉ में हालिया विकास पर विस्तार से चर्चा की और साइबर अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे पर चर्चा की। डॉ. दीक्षित ने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रमाणीकरण, संरक्षण और स्वीकार्यता की प्रक्रियाओं को समझाया और डिजिटल साक्ष्यों के संचालन और मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया।

सत्र का एक प्रमुख आकर्षण संजयसिंह राम. राव चव्हाण बनाम दत्तात्रेय गुलाबराव फाल्के खड।छन्/६/0040/2015, सहित कई ऐतिहा.

सिक मामलों पर चर्चा थी, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड की गई बातचीत की स्वीकार्यता पर निर्णय दिया था। इस बात पर जोर दिया गया कि मूल ध्वनि रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किए बिना, अनुवादित लिप्यंतरण प्रामाणिक नहीं होते और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डॉ. दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया कि स्रोत और प्रामाणिकता इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साक्ष्यात्मक मूल्य को निर्धारित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं।

कार्यक्रम में इंटरैक्टिव चर्चाएँ, केस विश्लेषण और व्यावहारिक प्रदर्शन शामिल थे, जिससे प्रतिभागियों को डिजिटल फॉरेंसिक और साक्ष्य मूल्यांकन की जटिलताओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ। अदालत में डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, विश्लेषण और प्रस्तुति के लिए वास्तविक दुनिया के अनुभव और सर्वोत्तम अभ्यास साझा किए गए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सत्र न केवल सैद्धांतिक, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी समृद्ध हों। प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम के व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।

कार्यक्रम का समापन सोनिया गुप्ता द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने डॉ. निशीथ दीक्षित को उनकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तथा न्यायिक अधिकारियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने अकादमी के कर्मचारियों के योगदान की भी सराहना की, जिनके प्रयासों से प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित हुआ। इस सत्र को साइबर कानूनों और डिजिटल साक्ष्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में न्यायिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।

रामबन में खूनी नाले में भूस्खलन से बिचालरी नदी अवरुद्ध; निचले इलाकों के गांवों को खतरा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू एवं कश्मीर के रामबन जिले के खूनी नाला क्षेत्र में गुरुवार को भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, जिससे बिचालरी नदी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि मलबे के कारण नदी पर बांध बन गया है और पानी जमा होने से निचले इलाकों के गांव, विशेषकर 20 घरों वाला करलाना गांव, अब बाढ़ के खतरे में है।

भूस्खलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है।

रियासी और रामबन जिलों के दूरदराज के गांवों में भारी बारिश के कारण शनिवार को बादल फटने और भूस्खलन की दो घटनाओं में एक ही परिवार के सात सदस्यों सहित कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले एक पखवाड़े में कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे जम्मू-कश्मीर में जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

केंद्र शासित प्रदेश 14 अगस्त से बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जूझ रहा है। ताजा घटनाओं के साथ, जम्मू में 130 लोगों की जान चली गई है और 140 घायल हो गए हैं, जबकि 32 तीर्थयात्री अभी भी लापता हैं।

रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थयात्रा शनिवार को पाँचवें दिन भी स्थगित रही। मंगलवार को कटरा से मंदिर तक के 12 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते में लगभग आधे रास्ते में भूस्खलन होने से 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अधिकारियों को स्थिति पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने तथा जोखिमग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को समय पर निकालने का निर्देश दिया है।

इस सप्ताह के शुरू में जम्मू क्षेत्र में हुई रिकॉर्ड बारिश ने भारी तबाही मचाई, सैकड़ों संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गईं और दर्जनों सड़कें तथा पुल बह गए, जिससे प्रमुख राजमार्गों पर यातायात स्थगित करना पड़ा, साथ ही रेल यातायात भी लगभग ठप्प हो गया।

वैष्णो देवी यात्रा पांचवें दिन भी स्थगित रही



सबका जम्मू कश्मीर

कटरा/जम्मू : बारीदार समुदाय के सदस्यों के एक समूह ने शनिवार को श्री माता वैशो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और रियासी जिले में मंदिर जाने वाले पुराने मार्ग पर हाल ही में हुए भूस्खलन की निष्पक्ष जांच की मांग की। इस भूस्खलन में 34 तीर्थयात्री मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए।

वैष्णो देवी तीर्थयात्रा शनिवार को लगातार पांचवें दिन भी स्थगित रही, जिससे सैकड़ों तीर्थयात्री कटरा में फंस गए, जो हाल ही में क्षेत्र में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद सड़क और रेल मार्ग से कटा हुआ है।

बारीदार समुदाय में वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े पुजारियों के परिवार शामिल हैं। काले झंडे लेकर और मंदिर बोर्ड के खिलाफ नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में बारीदार सड़कों पर उतर आए और बोर्ड के पुनर्गठन की मांग की, जिसमें स्थानीय विधायक और सांसद के अलावा उनके समुदाय के दो सदस्यों को भी शामिल किया जाए।

बारीदार संघर्ष समिति के अध्यक्ष शाम सिंह ने कहा, घूम 30 अगस्त को मंदिर बोर्ड के गठन के विरोध में और अपने अधिकारों की बहाली की मांग के समर्थन में काला दिवस मनाते रहे हैं। इसी दिन 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने हमें जबरन बाहर निकाल दिया था और मंदिर पर कब्जा कर लिया था।

26 अगस्त को भूस्खलन में तीर्थयात्रियों की दुखद मौत के लिए मंदिर बोर्ड को दोषी ठहराते हुए सिंह ने कहा कि बारीदार समुदाय इस त्रासदी के संबंध में मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा दिए गए जांच के आदेश को अस्वीकार करता है।

सिंह ने दावा किया, भ्रामले को दबाने के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों को जाँच सौंपी गई। अगर सरकार यह दावा कर रही है कि यात्रा पहले ही स्थगित कर दी गई थी, तो उसे तुरंत निष्पक्ष जाँच का आदेश देना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि तीर्थयात्री ट्रैक पर क्यों थे।

जाविद डार ने रामबन, रियासी की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जाविद अहमद डार ने रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जाविद डार ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

मंत्री ने आश्वासन दिया कि उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ मजबूती से खड़ी है तथा प्रभावित लोगों को हर

संभव सहायता प्रदान कर रही है।

प्रशासन सभी प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है।

जम्मू-कश्मीर सरकार प्रभावित परिवारों को समय पर राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राणा ने रियासी और रामबन में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने रियासी और रामबन जिलों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं में हुई दुखद जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्राकृतिक आपदाओं ने अनेक लोगों की जान ले ली है, परिवार तबाह हो गए हैं तथा समुदाय सदमे में हैं।

अपने भावपूर्ण संदेश में, मंत्री ने कहा, रियासी

और रामबन में विनाशकारी बादल फटने और भूस्खलन के बाद हुई जान-माल की हानि से मैं बेहद दुखी हूँ। इस गहन दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएँ।

राणा ने त्रासदी की गंभीरता तथा प्रभावित परिवारों पर पड़े भावनात्मक प्रभाव को स्वीकार किया।

उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों, पुलिस और जिला प्रशासन सहित बचाव दलों की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की, जो प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाने, तलाशी अभियान चलाने तथा

चिकित्सा एवं रसद सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है तथा राहत एवं पुनर्वास के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके अधीन सभी विभाग यथाशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए समन्वित प्रयास करेंगे।

राणा ने जनता से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा प्रशासन द्वारा जारी सुझाव सलाह का पालन करने की भी अपील की।



साप्ताहिक

सबका जन्मू कश्मीर
संपादकीय

आपदा और लापरवाही



संपादक - राज कुमार

पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को नया रूप देने वाला एक तात्कालिक संकट है। 30 से ज्यादा लोगों की जान जाने, 3,50,000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित या प्रभावित होने, आर सभा 23 ज़िला को बाढ़ प्रभावित घोषित किए जाने के साथ, राज्य 1988 के बाद से अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उससे न केवल उसके निवासियों को, बल्कि पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यह आपदा भारत की खाद्य सुरक्षा के मूल में है। पंजाब को देश की ख्याति टोकरी के रूप में जाना जाता है, वह भूमि जिसने दशकों से गेहूँ और चावल का उत्पादन किया है जो भारतीयों की थाली भरते हैं। आज, लगभग 1,50,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि जलमग्न है, और जो फसलें कभी जीविका का वादा करती थीं, वे बाढ़ के पानी में समा गई हैं। ऐसे राज्य में जहाँ एक-चौथाई आबादी सीधे कृषि पर निर्भर है, यह आजीविका के लिए एक बड़ी आपदा है। हजारों किसान अब आय के नुकसान, बढ़ते कर्ज और बिखरते भविष्य की भयावह संभावना का सामना कर रहे हैं। प्रतिक्रिया का पैमाना बहुत बड़ा रहा है। सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा समर्थित आपदा प्रतिक्रिया दल, परिवारों और पशुओं को बचाने के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों के साथ तैनात किए गए हैं। राहत शिविर आश्रय, भोजन और दवाइयाँ तो प्रदान करते हैं, लेकिन वे उस क्षति की भरपाई नहीं कर सकते जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है - घर नष्ट हो गए, संपत्ति बह गई और कृषि चक्र बाधित हो गया। कई परिवारों के लिए, रेत की बोरियों से तटबंधों की मरम्मत करना और उफनती नदियों के किनारे पहरा देना ही जीवन और निराशा के बीच एकमात्र बचाव बन गया है। हालाँकि इसे एक असाधारण आपदा के रूप में देखना आकर्षक लगता है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। पंजाब की बाढ़ एक पैटर्न का हिस्सा है। मौसम विज्ञानी अत्यधिक वर्षा के लिए मानसूनी धाराओं और पश्चिमी विक्षोभ के बार-बार टकराव को जिम्मेदार ठहराते हैं, एक ऐसी गतिशीलता जो जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम प्रणालियों में बदलाव के साथ और भी अधिक बार होती जा रही है। अत्यधिक वर्षा, अचानक बाढ़ और जलाशयों का भर जाना अब असामान्य नहीं हैं, ये नई सामान्य स्थिति हैं। सीमा पार पाकिस्तान में पंजाब प्रांत भी इसी तरह की कठिन परीक्षा का सामना कर रहा है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि जलवायु परिवर्तन राजनीतिक सीमाओं की परवाह नहीं करते। यह संकट हमें कठिन प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है। हम उस बुनियादी ढाँचे पर क्यों निर्भर रहते हैं जो साल-दर-साल दबाव में कमजोर पड़ता जाता है? हम बाढ़ के मैदानों में जोखिम जानते हुए भी अनियंत्रित निर्माण की अनुमति क्यों देते हैं? और जब आपदाएँ इतनी अप्रत्याशित रूप से आती हैं, तो राष्ट्रीय नियोजन में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन अब भी एक गौण विचार क्यों है? पंजाब की त्रासदी भारत के लिए एक चेतावनी बननी चाहिए। केंद्रीय सहायता, जिसकी अभी तत्काल आवश्यकता है, केवल राहत और मुआवजे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे नदी प्रबंधन, लचीली फसल प्रणालियों, किसानों के लिए बीमा व्यवस्था और जल-सम्बन्धी शहरी नियोजन में दीर्घकालिक निवेश में परिवर्तित होना चाहिए। अन्यथा, विनाश और पुनर्निर्माण का चक्र बार-बार दोहराया जाएगा, हर बार अधिक कीमत पर। बाढ़ प्रकृति का एक कृत्य हो सकता है, लेकिन इससे होने वाली पीड़ा मानवीय उपेक्षा से और भी बढ़ जाती है। यदि भारत इस क्षण को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में नहीं लेता है, तो पंजाब का बाढ़ का पानी न केवल फसलों और घरों को डुबो देगा, बल्कि जलवायु-आधारित भविष्य के लिए देश की तैयारियों में विश्वास को भी नष्ट कर देगा।

1990 के दशक की शुरुआत में एक बच्चे के रूप में बड़े होते हुए, मुझे स्कूल में ग्रीनहाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा हुआ याद है। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह के पास गर्मी को फँसाती है, जैसे ग्रीनहाउस का कांच।

मिकी मोरी

1990 के दशक की शुरुआत में एक बच्चे के रूप में बड़े होते हुए, मुझे स्कूल में ग्रीनहाउस प्रभाव के बारे में सीखना याद है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह के पास गर्मी को फँसाती है, जैसे ग्रीनहाउस का कांच। मैंने खुद को खेल के मैदान पर, एक नम गर्म घर के अंदर तपते हुए कल्पना की। 30 साल आगे बढ़ते हुए, और शब्द बदल गए हैं। कुछ समय के लिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते वैश्विक तापमान और मानवीय गतिविधियों की भूमिका, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में बात करने के लिए जाने-माने शब्द थे।

2007 में इंटरनेट पर इसकी खोज में तेजी आई थी, संभवतः पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर की डॉक्यूमेंट्री 'एन इनकम्प्लीट हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग' के कारण, जो 2006 में सिनेमाघरों में आई थी। ओबामा प्रशासन के अंत के करीब, ग्लोबल वार्मिंग सबसे आम शब्द बन गया। यह अब ग्लोबल वार्मिंग से ज्यादा व्यवहार्य सच में ट्रेंड कर रहा है। दोनों शब्द एक ही बात कहते हैं, बढ़ते वैश्विक तापमान का स्थानीय मौसम पैटर्न और दुनिया भर में जलवायु प्रभावों पर बड़ा असर पड़ता है, जिसमें तेज तूफान, सूखा, बाढ़ और आग शामिल हैं।

ग्लोबल ट्रेंड्स समय के साथ इंटरनेट सर्च शब्दों की सापेक्ष लोकप्रियता को ट्रैक करता है। हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग शब्द की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर कम हुई है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग की लोकप्रियता बढ़ी है। हालाँकि, इन प्रभावों पर चर्चा करने के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वे लोगों के जोखिमों और अधिक टिकाऊ विकल्पों की आवश्यकता को समझने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। मैं एक भाषा विज्ञान शोधकर्ता हूँ जो वर्तमान में मेडागास्कर के तट से दूर मायोट द्वीप पर रहता हूँ, जहाँ मैं स्थानीय आबादी के बीच जलवायु परिवर्तन के ज्ञान और इस पर चर्चा करने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा का अध्ययन करता हूँ। मायोट में स्थानीय मछुआरे इस घटना के बारे में बात करने में संघर्ष करते हैं क्योंकि इसके लिए कोई स्थापित शब्दावली नहीं है।

मेरे सहकर्मियों और मैंने जो सीखा है, उससे कई संस्कृतियों में लोगों को जलवायु परिवर्तन को समझने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जलवायु परिवर्तन शिक्षा और स्थिरता प्रयासों की भव्य योजना में, अनुवाद की यह छोटी सी समस्या वास्तव में मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के बारे में एक बड़े अंतर्निहित मुद्दे का लक्षण है। वास्तव में, जब हम संस्कृतियों में जलवायु परिवर्तन के बारे में संवाद करने की चुनौतियों में गहराई से उतरते हैं, तो दो कारक सामने आते हैं: आध्यात्मिक विश्वास और

समय की धारणाएँ।

आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताएँ जलवायु परिवर्तन को समझने और यहाँ तक कि नाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उदाहरण के लिए, कनाडा में बोली जाने वाली इनुइट भाषा इनुविटुट में जलवायु शब्द का अनुवाद 'सिला' है। हालाँकि, सिला का अर्थ ज्ञान, आत्मा, पृथ्वी और ब्रह्मांड भी है। यह पूजनीय चीज़ है। परिभाषाओं के इस दूसरे सेट के लेंस के माध्यम से देखा जाए तो सिला को लोगों द्वारा प्रभावित करना प्रभावी रूप से असंभव है। ब्रह्मांड को बदलना मानव जाति की पहुँच से परे है। परिणामस्वरूप, जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचार पूर्वी कनाडाई इनुइट भाषाओं में राजनीतिक हो जाता है। मेरे सहकर्मियों और मुझे मैयट में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले पर्यावरणीय विनाश को धीमा करने के संभावित भविष्य के प्रयासों पर चर्चा करते समय इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमने जिन माओरी मछुआरों का साक्षात्कार लिया, उनमें से कई गहरी इस्लामी आस्था वाले थे, जब उनसे भविष्य में समुदाय द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अक्सर 'इशाल्लाह' या ईश्वर की इच्छा से जवाब दिया। उन्होंने इन जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटनाओं को अपने हाथ से बाहर माना, क्योंकि केवल ईश्वर ही इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, हम सोच सकते हैं कि समय वस्तुनिष्ठ है और इसलिए संस्कृतियों में साझा किया जाता है।

लेकिन जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने तर्क दिया, समय सापेक्ष है। समय न केवल वैज्ञानिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनानियों के पास तीन से अधिक प्रकार के समय थे, जिनमें से एक का हम आज भी उपयोग करते हैं, क्रोनोस, या रैखिक समय - कालानुक्रमिक क्रम के बारे में सोचें। हम सभी एयन, या पवित्र, शाश्वत समय, और कैरोस, या चक्रीय समय को भूल चुके हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचते समय समय की धारणाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इस घटना का मूल एक लंबी अवधि में धीमा, निरंतर परिवर्तन है। हम जलवायु परिवर्तन को नंगी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि यह वर्षों और दशकों में होता है।

बेशक, हम मौसम के पैटर्न पर इसके प्रभाव देख सकते हैं, जिसमें अत्यधिक गर्मी की लहरें और भारी बारिश शामिल हैं। लोगों को समय के बारे में इस तरह से सोचने के लिए प्रेरित करना कि वे एक साथ वर्तमान और दूर के भविष्य के बारे में सोचें, कई संस्कृतियों में चुनौतीपूर्ण साबित होता है। उदाहरण के लिए, मालदीव द्वीप समूह में स्थिरता के प्रयासों का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को इसी मुद्दे का सामना करना पड़ा है। समय पर चर्चा करते समय, कई स्थानीय निवासी वर्तमान और निकट

भविष्य के संदर्भ में सोचते हैं, जबकि नीति निर्माताओं को बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए। समय के इन विपरीत दृष्टिकोणों ने बढ़ते समुद्र के स्तर से निपटने के लिए स्थिरता प्रयासों को लागू करना मुश्किल बना दिया है - जो 26 एटोल वाले इस उष्णकटिबंधीय देश के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इस समस्या का सामना करने के लिए पहला कदम जलवायु परिवर्तन शिक्षा प्रयासों में भाषा को सबसे आगे रखना है। इस क्षेत्र में कदम रखने वाला एक युवा-संचालित गैर-लाभकारी संगठन क्लाइमेट कार्डिनल्स है। समूह का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन अनुसंधान को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाओं में अनुवादित करना है। अधिकांश वैज्ञानिक अध्ययन और रिपोर्ट अंग्रेजी में हैं, जो दुनिया भर में कई गैर-अंग्रेजी बोलने वालों के लिए एक बाधा हो सकती है। इस शोध और संबंधित घटनाओं का अनुवाद करने के अपने प्रयासों में, उन्हें इस बारे में सावधानी से सोचने की ज़रूरत है कि महत्वपूर्ण शब्दों का अनुवाद और समझ कैसे की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र और अन्य समूह भी जलवायु परिवर्तन संदेह और धर्म के बीच संबंध को गंभीरता से लेना शुरू कर रहे हैं, जिसमें अंततः टकराव के बिंदुओं को समेटने की आवश्यकता भी शामिल है।

उदाहरण के लिए, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर स्थिरता प्रयासों और आस्था की अनुकूलता को संबोधित करता है। यह धार्मिक नेताओं को समुदाय के पर्यावरण के साथ देखभाल और लालच को अस्वीकार करने जैसे मूल आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ने में मदद करके ऐसा करता है, इस प्रकार प्रकृति के साथ फिर से जुड़ता है और खुद को इसके संरक्षक के रूप में देखता है। अंत में, परिवर्तन और समय से संबंधित पर्यावरण के बारे में स्थानीय या स्वदेशी ज्ञान का अध्ययन करते रहना अनिवार्य है। प्राचीन यूनानियों के पास निश्चित रूप से समय को कई श्रेणियों में विभाजित करने के अपने कारण थे। तो वे कौन से पर्यावरणीय और ऐतिहासिक प्रभाव थे जिन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में शोधकर्ता और समुदाय के सदस्य स्वदेशी ज्ञान को पश्चिमी विज्ञान के साथ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा कई पीढ़ियों से अपने पर्यावरण के दीर्घकालिक अवलोकन के कारण, वे जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों की पहचान करने में सक्षम थे।

ऐसी जानकारी को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और पारंपरिक शोध विधियों द्वारा प्राप्त करना मुश्किल होता है। जलवायु परिवर्तन जागरूकता और स्थिरता के प्रयास समय के साथ ही बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इन अवधारणाओं को गैर-पश्चिमी परिवेश में कैसे जिया, समझा और बात की जाती है।

डॉ. ताहिर चौधरी ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को अपशब्द कहना लोकतंत्र पर धब्बा है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की श्रमदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है।

भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता डॉ. ताहिर चौधरी ने कहा कि यह घटना कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में उसके सहयोगियों के नैतिक पतन को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, प्यार न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का अपमान है, बल्कि इस देश के हर उस नागरिक का अपमान है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है। मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल शर्मनाक और अस्वीकार्य है।

डॉ. चौधरी ने राहुल गांधी पर राजनीतिक विमर्श में नफरत और गाली-गलौज की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, कांग्रेस एक गली-पार्टी बन गई है। उनके नेताओं के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, विकास के लिए कोई विजन



नहीं है, इसलिए वे घटिया गालियाँ दे रहे हैं। यह लोकतंत्र की राजनीति नहीं, बल्कि हताशा की राजनीति है। उन्होंने कहा कि बिहार और पूरे देश की जनता आगामी चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को 'करारा जवाब' देगी।

डॉ. चौधरी ने कहा, पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। विपक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही कि कैसे एक गरीब माँ का बेटा वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करने के लिए आगे आया। उनके बार-बार के हमले उनकी हताशा

को ही उजागर करते हैं।

भाजपा नेता ने चुनाव आयोग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा, भारतीय लोकतंत्र में बहस की जगह गालियों को जगह नहीं दी जा सकती। इस तरह का व्यवहार राजनीति की गरिमा को कम करता है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल ढांचे को नुकसान पहुँचाता है। डॉ. चौधरी ने कांग्रेस को यह भी याद दिलाया कि भारत की संस्कृति हमेशा से ही राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बुजुर्गों के प्रति सम्मान पर आधारित रही है।

उन्होंने कहा, फटितनत युद्धों में भी, नेताओं ने कभी परिवारों को राजनीति में नहीं घसीटा। दरभंगा में जो हुआ वह न केवल मोदी जी का अपमान है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक कलंक है।

डॉ. चौधरी ने लोगों से राहुल गांधी द्वारा प्रचारित धृष्टता की राजनीति के प्रति सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा विकास, सशक्तिकरण और एकता पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी, जबकि विपक्ष ने नकारात्मकता का रास्ता चुना है।

अशोक कौल ने श्रीनगर में भाजपा संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता की, नेतृत्व ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की



सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जम्मू और कश्मीर ने महासचिव (संगठन) अशोक कौल के नेतृत्व में श्रीनगर के चर्च लेन में एक संगठनात्मक बैठक बुलाई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करना, समन्वय को सुव्यवस्थित करना तथा कश्मीर क्षेत्र में भाजपा की उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करना था।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, अशोक कौल ने एक मजबूत और अनुशासित संगठनात्मक ढाँचे की आवश्यकता पर जोर दिया, जो उनके अनुसार पार्टी के बढ़ते दायरे की रीढ़ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा का विकास जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण, लोगों के साथ निरंतर संवाद और पार्टी के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।

बैठक में भाजपा के प्रदेश महासचिव अनवर खान, भाजपा सचिव मुदासिर वानी और आरिफ राजा, तथा सभी प्रकोष्ठों के सह-प्रभारी बिलाल पारं सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। पार्टी के आधार का विस्तार करने, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने और आगामी पहलों के क्रियान्वयन में एकजुट और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा हुई।

अशोक कौल ने क्षेत्र के कोने-कोने तक भाजपा का संदेश पहुँचाने में पार्टी पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और उनसे नए जोश और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का अंतिम उद्देश्य निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना और जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक शासन की भावना को मजबूत करना है। बाद में, अशोक कौल वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ गुजरबल नूरबाग स्थित हबीबुल्लाह शाह के आवास पर गए। वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाम नबी पालपोरी के ससुर शाह का आज सुबह संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। नेताओं ने परिवार को इस कठिन समय में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

अल्लाफ ठाकुर ने बाढ़ से निपटने के उपायों की कमी को लेकर उमर सरकार की आलोचना की

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के जम्मू-कश्मीर प्रवक्ता अल्लाफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह बाढ़ से निपटने के लिए कोई योजना बनाने में पूरी तरह विफल रही है, जबकि घाटी में दो दिन की बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लोगों और अधिकारियों को आपात स्थिति के लिए तैयार करने हेतु एक भी मॉक ड्रिल नहीं की है, तथा प्रशासन ने 2014 की विनाशकारी बाढ़ से कोई सबक नहीं सीखा है। ठाकुर ने कहा, जब भी भारी बारिश होती है, कश्मीर के लोग लगातार डर के साये में जी रहे हैं।

सरकार कोई दीर्घकालिक रणनीति बनाने में नाकाम रही है, न ही उसने मॉक ड्रिल आयोजित करने की ज़रूरत उठाई है, जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ज़रूरी है।

उन्होंने अधिकारियों से झेलम नदी की सफाई, तटबंधों को मजबूत करने तथा उचित आपदा तैयारी योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने का आग्रह किया तथा चेतावनी दी कि आगे कोई भी लापरवाही 2014 के पैमाने की एक और त्रासदी का कारण बन सकती है।

पवन शर्मा ने सरकार से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया

भाजपा जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के भाजपा वरिष्ठ नेता और राज्य सचिव पवन शर्मा ने केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ के बाद उभरते सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि जान-माल की भारी क्षति के अलावा, बाढ़ ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को भी बाधित कर दिया है, जिससे हजारों प्रभावित परिवार जल जनित बीमारियों, संक्रमण और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की कमी जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं।

बाढ़ के बाद जन स्वास्थ्य के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को स्वास्थ्य विभाग को तुरंत निर्देश देना चाहिए कि वह सभी बाढ़



प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करे। पर्याप्त चिकित्सा दल, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ, आवश्यक दवाएँ और

आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र बिना किसी देरी के तैनात किए जाने चाहिए। शर्मा ने कहा।

उन्होंने प्रशासन से स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए निवारक जागरूकता अभियान शुरू करने का आग्रह किया।

चल रहे राहत और बचाव कार्यों की सराहना करते हुए, शर्मा ने जोर देकर कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों के संभावित प्रकोप को रोकने के लिए समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाजपा इस कठिन समय में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर मंच पर उनकी चिंताओं को उठाती रहेगी।

खराब मौसम के बीच सीएम ने जोखिम वाले क्षेत्रों से लोगों को समय पर निकालने का निर्देश दिया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू एवं कश्मीर में खराब मौसम के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को अधिकारियों को चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करने और जोखिम वाले क्षेत्रों से निवासियों को समय पर निकालने का निर्देश दिया।

यह बयान रामबन और रियासी जिलों में बादल फटने और भूस्खलन की दो ताजा घटनाओं के बाद आया है, जिसमें एक ही परिवार के सात सदस्यों सहित 11 लोगों की

मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया।

मुख्यमंत्री ने दुखद मौतों पर दुख व्यक्त किया।

रामबन के राजगढ़ में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया, जबकि रियासी जिले के माहौर इलाके के बह्र गांव में भूस्खलन में एक दंपति और उनके पांच बच्चे जिंदा दफन हो गए।

लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने, संवेदनशील क्षेत्रों से बचने और सुरक्षा सलाह का सख्ती से पालन करने की अपील की।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उन्होंने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जमीनी स्तर पर मौजूद रहें, चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित करें, जोखिम वाले क्षेत्रों से निवासियों को समय पर निकालें और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और हर संभव सहायता प्रदान करें।

अब्दुल्ला ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने, निकट समन्वय स्थापित करने तथा खराब मौसम में जान-माल की सुरक्षा के लिए हर एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

उमर सरकार ने राहत और पुनर्वास के लिए 200 करोड़ रुपये जारी किए, भाजपा एक दशक से चली आ रही लापरवाही के लिए जवाबदेह : सधोत्रा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव और पूर्व मंत्री श्री अजय कुमार सधोत्रा घने आज मद्र विधानसभा क्षेत्र के तवी द्वीप क्षेत्र का दौरा किया, जो हाल ही में आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं का राजनीतिकरण करने के प्रयास पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने भाजपा के बयानों को अवसरवादी, भ्रामक और जमीनी तथ्यों से परे बताया।

भाजपा की अनुचित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, श्री सधोत्रा घने कहा कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को बदनाम करने का भाजपा का प्रयास न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि उन लोगों का अपमान भी है जो अभी भी बाढ़, भूस्खलन और बाढ़ फटने से हुई तबाही से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब जनाब उमर अब्दुल्ला के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरी सरकार और लोग राहत और पुनर्वास के लिए एकजुट हैं, भाजपा ने विभाजनकारी आरोप-प्रत्यारोप का रास्ता चुना है।

श्री सधोत्रा घने याद दिलाया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने रामबन और चेसोटी भूस्खलन के बाद तत्काल पुनर्निर्माण कार्यों और चुनौतियों के साथ-साथ ऑपरेशन सिंधुर से हुए नुकसान के लिए 200 करोड़ रुपये जारी किए थे। मुख्यमंत्री स्वयं पूरी तरह सतर्क हैं, लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों तक राहत पहुँचे। उन्होंने कहा कि मंत्री और अधिकारी चौबीसों घंटे ज़मीन पर मौजूद हैं और



बचाव, राहत और बहाली के प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार प्रेस रूम से बयान जारी करने में नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखती है। तवी नदी पर चौथे पुल के ढहने की भाजपा की आलोचना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, श्री सधोत्रा घने याद दिलाया कि यह पुल एक दशक से भी पहले गैर-नेशनल कॉन्फ्रेंस शासन के दौरान बनाया गया था। भाजपा अंधेरे में तीर चला रही है। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि जब इतनी बड़ी बाढ़ और बाढ़ फटने की घटनाएँ होती हैं, तो कोई भी पुल, तटबंध या संरचना प्रकृति के प्रकोप का सामना नहीं कर सकती। नेकों के अतिरिक्त महासचिव ने अवैध खनन को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी को किसी पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सच्चाई यह है कि पिछले एक दशक में भाजपा केंद्र और जम्मू-कश्मीर दोनों जगहों पर सत्ता में रही है। उन्होंने निवारक उपाय विकसित करने, तटबंधों को मज़बूत करने या अवैध खनन को

रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जिससे नदी तल कमजोर हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज का नुकसान वास्तव में भाजपा की आपराधिक लापरवाही और नीतिगत निष्क्रियता का सीधा परिणाम है।

नेकों के मंत्रियों को भाजपा द्वारा षौर-निष्पादित संपत्ति बताए जाने को हताशा का संकेत बताते हुए, श्री सधोत्रा घने कहा, प्यह नेकों सरकार ही थी जो प्राकृतिक प्रकोप के सामने डटी रही, धनराशि जारी की, प्रशासन को सक्रिय किया और पीड़ितों तक पहुँची। दूसरी ओर, भाजपा, दस साल से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद, सुरक्षा उपाय बनाने, बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने या प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयारी करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि अब वे बेशर्मी से अपनी नाकामियों का ठीकरा उमर अब्दुल्ला सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सधोत्रा घने भाजपा को आगाह किया कि वह लोगों को गुमराह करना बंद करे और राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता की माँग करे। तवी द्वीप के लोगों को अपनी संपत्ति,

सामान और फसलों का भारी नुकसान हुआ है, इसके अलावा कई खेतों में गाद भर गई है और किसानों के लिए अपनी खेती करना मुश्किल हो गया है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री प्रसाद से बात की क्योंकि पिछले पाँच दिनों से बिजली और पानी नहीं है। उन्होंने मुख्य अभियंता पीएचई श्री हनीफ से भी पानी की आपूर्ति तुरंत बहाल करने के लिए बात की। उन्होंने एसडीएम दक्षिण श्री मनु से भी बात की और उनसे राजस्व कर्मचारियों द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान का गहन सत्यापन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, प्जम्मू-कश्मीर के लोगों को नारों की नहीं, बल्कि समर्थन की ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि भाजपा घड़ियाली औसू बहाना बंद करे और मौजूदा नुकसान की ज़िम्मेदारी स्वीकार करे। श्री सधोत्रा घने जम्मू-कश्मीर के लोगों से भाजपा की ध्यान भटकाने वाली राजनीति को समझने और चुनावी लाभ के लिए मानवीय त्रासदी का फायदा उठाने वालों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई एकजुट होनी चाहिए – प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ और जीवन के पुनर्निर्माण के लिए – न कि दोषारोपण और राजनीतिक अवसरवाद की राजनीति से विभाजित।

उनके साथ मौजूद अन्य लोगों में रघबीर सिंह मन्हास, जिला अध्यक्ष जम्मू ग्रामीण अ, राकेश शर्मा (फलवान) जिला अध्यक्ष जम्मू ग्रामीण अ, युवा कांग्रेस, बारो राम उपाध्यक्ष जिला जम्मू ग्रामीण अ, कृष्ण दास भगत ब्लॉक अध्यक्ष, रणधीर सिंह जिला सचिव जम्मू ग्रामीण अ, खजूर राज सरपंच, मन मोहन आयोजक, करण सिंह, देविंदर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष मथवार, संदीप मन्हास, वीर जी भट, आशानंद, सतपाल पंच शामिल थे।

राणा ने बाढ़ प्रभावित जम्मू में जलापूर्ति बहाली की समीक्षा की

बाढ़ प्रभावित जल आपूर्ति अवसंरचना को बहाल करने के लिए तेजी से प्रयास जारी

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के सक्रिय प्रयास में, जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने प्रमुख अधिकारियों, विधायकों और जिला प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक का मुख्य उद्देश्य हाल ही में आई बाढ़ के कारण बाधित हुई जल आपूर्ति सेवाओं का आकलन करना तथा उनकी बहाली में तेजी लाना था।

बैठक में डीडीसी अध्यक्ष भारत भूषण, विधायक चौ. विक्रम रंधावा, अरविंद गुप्ता, शाम लाल शर्मा, डॉ. नरिंदर सिंह, उपायुक्त जम्मू, आयुक्त जम्मू नगर निगम, आईएंडएफसी, जल शक्ति और यूईईडी जम्मू के मुख्य अभियंताओं के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंताओं सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सत्र के दौरान, मंत्री को चल रहे पुनर्स्थापन प्रयासों, अब तक हुई प्रगति, सामने आई चुनौतियों तथा राहत कार्यों में तेजी लाने और सामान्य जल आपूर्ति बहाल करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी गई।

राणा ने जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।



मंत्री ने उन इलाकों में तुरंत पानी के टैंकर तैनात करने के निर्देश दिए जहाँ पानी की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है। उन्होंने मौजूदा टैंकरों के बेड़े को बढ़ाने और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम आधार पर निजी पानी के टैंकरों का उपयोग करने की भी सिफारिश की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उन क्षेत्रों में अग्निशमन गाड़ियों के उपयोग का प्रस्ताव रखा जहाँ टैंकर नहीं पहुँच सकते, ताकि प्रभावित समुदायों को पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

बहाली के प्रयासों को सुचारू बनाने के लिए, मंत्री राणा ने विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा बहाली कार्य को समय पर पूरा करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने मुख्य अभियंता को बहाली कार्यों के वितरण की देखरेख करने तथा बहाली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने का निर्देश दिया। बैठक में शामिल

विधायकों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की चुनौतियों पर बात की और पानी की आपूर्ति में तेजी लाने का आग्रह किया।

उन्होंने उन क्षेत्रों का जिक्र किया जहाँ पानी की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित है और तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया।

जवाब में, मंत्री महोदय ने विधायकों को आश्वासित किया कि उनकी चिंताएँ सरकार के लिए प्राथमिकता हैं। उन्होंने यह भी आश्वासित किया कि इन समस्याओं के समाधान और पुनर्निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं।

राणा को बताया गया कि शीतली में जलापूर्ति योजना का जीर्णोद्धार कार्य वर्तमान में दो पालियों में चल रहा है तथा पांच दिनों के भीतर इसे पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) को जल शक्ति विभाग द्वारा चिन्हित समर्पित फीडर लाइनों को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया गया है, जो प्रभावित

क्षेत्रों में जल आपूर्ति की बहाली के लिए महत्वपूर्ण है।

शहरी पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग (यूईईडी) को बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से संबंधित विधायक के साथ मिलकर नालों के निर्माण और बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान विकसित करने का काम सौंपा गया है।

इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तथा दीर्घावधि में उसे बहाल किया जाए।

इससे पहले, मंत्री ने जम्मू के बठिंडी हाइड्रो का दौरा कर जनता की शिकायतें सुनीं। पूर्व विधायक टीएस टोनी और जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, राणा ने निवासियों को आश्वासित किया कि सरकार पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राणा ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, विशेषकर बाढ़ के बाद, सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित जलापूर्ति अवसंरचना को शीघ्र बहाल करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

सरकार शीघ्र बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा सभी हितधारकों के सहयोग से इसका लक्ष्य प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल करना है।

डीसी कुपवाड़ा ने भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण केंद्रों का निरीक्षण किया

जियारत मुकाम शाहवली में व्यवस्था, निर्माण कार्य की समीक्षा की



सबका जम्मू कश्मीर

कुपवाड़ा : उपायुक्त (डीसी) कुपवाड़ा, श्रीकांत बालासाहेब सुसे ने आज जमाबंदी और मसा. विस के डिजिटलीकरण की प्रगति का आकलन करने के लिए तहसील कुपवाड़ा और ड्रगमुल्ला में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण केंद्रों

का दौरा किया।

इस दौरान, उपायुक्त ने राजस्व कर्मचारियों से बातचीत की, फीडबैक लिया और डिजिटलीकरण प्रक्रिया में गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा

करने के निर्देश दिए।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्रुगमुला में स्थापित डिजिटलीकरण केंद्र में डीसी ने विद्यार्थियों से भी बातचीत की।

बाद में, उपायुक्त ने आगामी ईद-ए-मिलाद के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मोकाम द्रुगमुल्ला स्थित जियारत जेटी-शाह-वली का दौरा किया।

उन्होंने अधिकारियों को दरगाह के आसपास निर्बाध जल एवं विद्युत आपूर्ति, उचित साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

डीसी ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया।

डीसी के साथ सहायक आयुक्त राजस्व, तहसीलदार कुपवाड़ा, तहसीलदार ड्रगमुल्ला और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

मंडलायुक्त कश्मीर ने नारानाग से वार्षिक गंगबल यात्रा को हरी झंडी दिखाई



सबका जम्मू कश्मीर

गंदेरबल : कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग द्वारा गंदेरबल के नारानाग मंदिर से औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाने के बाद आज वार्षिक गंगबल यात्रा बड़े धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुई।

इस अवसर पर गांदरबल के उपायुक्त जतिन किशोर, एसएसपी गांद. रबल खलील पोसवाल के अलावा अन्य नागरिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

कश्मीरी पंडित समुदाय के तीर्थयात्रियों के एक समूह ने ऐतिहासिक नारानाग मंदिर से श्रद्धेय छड़ी पूजा के बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। एसडीआरएफ टीमों, पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ श्रद्धालु पवित्र गंगबल झील की 15 किलोमीटर की यात्रा पर निकले, जो हरमुख पर्वत श्रृंखला में लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।

इस अवसर पर बोलते हुए, मंडलायुक्त ने यात्रा की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने तीर्थयात्रियों और उनके साथ आए सहयोगी दलों को अपनी शुभकामनाएँ दीं।

पवित्र अनुष्ठान गंगबल झील के तट पर किए जाएंगे, जिसके बाद तीर्थयात्री अगले दिन वापस लौट आएंगे।

इस अवसर पर आयोजकों और श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और नारानाग के स्थानीय समुदाय के प्रति उनके अमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया, जो तीर्थयात्रा के सुचारु संचालन में सहायक रहे हैं। ध्वजारोहण समारोह के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त गंदेरबल, एसडीएम कंगन, एसडीपीओ कंगन, तहस. िलदार कंगन और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

डीजीपी, बीएसएफ एडीजी ने जम्मू बाढ़ के बाद भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा की



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात और बीएसएफ के एडीजी, पश्चिमी कमान, एसएस खंडारे ने जम्मू क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा की अलग-अलग समीक्षा की।

कठुआ और जम्मू जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर दोना. अधिकारियों का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संभावित यात्रा से एक दिन पहले हुआ है, जो इस सप्ताह के शुरू में हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा करेंगे। बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी और मौत और विनाश का तांडव मचा हुआ है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाढ़ से सीमा ग्रिड को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें बाढ़ और जम्मू, सांबा तथा कठुआ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर स्थित सीमा चौकियां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल स्थिति का फायदा उठाकर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की आतंकवादियों की किसी भी कोशिश को विफल करने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रभात ने जम्मू-सांबा-कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शोभित सक्सेना के साथ कठुआ के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और बीएसएफ अधिकारियों ने उन्हें बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी।

जनजातीय कार्य विभाग ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 2.53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की

राणा ने 5 सितंबर तक लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर जनजातीय मामलों के विभाग (टीएडी) ने अपनी छात्रवृत्ति योजना के तहत एसटी-2 छात्रों को 2.53 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की है, जो जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की शैक्षिक गतिविधियों का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने निर्देश दिया है कि सभी बकाया छात्रवृत्ति भुगतानों को 5 सितंबर, 2025 तक संसाधित और मंजूरी दे दी जाए। उन्होंने जनजातीय मामलों के निदेशक को निर्दिष्ट तिथि तक

गैर-लंबित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

राणा ने इससे पहले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के समय पर वितरण के महत्व पर जोर दिया था।

उन्होंने कहा कि ये छात्रवृत्तियाँ जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक उन्नति में सहायता करने के लिए सरकार की पहल का हिस्सा हैं।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियागत देरी के कारण किसी भी पात्र छात्र को उसकी उचित छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह कदम छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए सरकार के हालिया

निर्देशों के अनुरूप भी है।

राणा ने अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों, विशेषकर वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहे विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

उन्होंने कहा, प्यहल हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र एसटी छात्र को अपनी शिक्षा जारी रखने और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता मिले।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुचारु एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

सत शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां का अपमान करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां का अपमान करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में महिला मोर्चा नेताओं की एक संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जम्मू-कश्मीर भाजपा महासचिव संजीता डोगरा और बलदेव सिंह बिलावरिया, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष नेहा महाजन और पूरे क्षेत्र से वरिष्ठ महिला मोर्चा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए।

सत शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एक राजनीतिक रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

उनकी दिवंगत माँ के खिलाफ की गई अपमान. जनक टिप्पणियाँ धर्मानाक, अक्षम्य और सम्य लोकतंत्र में अस्वीकार्य हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी माँ का अपमान, चाहे वह जीवित हो या दिवंगत, भारत की संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए अनादर की संस्कृति का परिचय दिया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ को राजनीति में घसीटकर उन्होंने इस देश की हर माँ का अपमान किया है।

शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस का भारत माता से लेकर भारत में रहने वाली माताओं तक का अपमान करने का इतिहास रहा है और उन्होंने संकल्प लिया कि इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजीता डोगरा ने टिप्पणी की कि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्ढा, जो स्वयं

माँ हैं, को उस समय चुप रहने में शर्म आनी चाहिए जब किसी अन्य माँ के खिलाफ ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है।

बलदेव सिंह बिलावरिया ने कहा कि कांग्रेस ने शालीनता और राजनीतिक नैतिकता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं और इसके नेतृत्व को बिना देरी किए माफी मांगनी चाहिए।

नेहा महाजन ने कहा कि महिला मोर्चा यह सुनिश्चित करेगा कि जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को कांग्रेस के महिला विरोधी रुख के बारे में जागरूक किया जाए। भाजपा नेताओं ने आगामी पार्टी कार्यक्रमों पर भी चर्चा की, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं के साथ महिला मोर्चा के जुड़ाव को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिला शक्ति भाजपा की संगठनात्मक और सामाजिक शक्ति का केंद्र है।

साप्ताहिक राशिफल



मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको निजी जीवन से लेकर करियर-कारोबार तक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर-कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।



वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर-कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल-मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटक कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर-परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन-जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी-साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।



मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक-कार्यों में खूब रहेगा। किसी धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. बले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।



कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।



सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुनी पड़ सकती है।



कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद-विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।



तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते-नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।



वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता-सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन-पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।



धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता है। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।



मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर-कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आए अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।



कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल-मिलाप बढ़ेगा। आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।



मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी-रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा।

एफआईसीसीआई फ्लो जेकेएल ने जीसीडब्ल्यू परेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवा महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, फिककी एफएलओ जम्मू कश्मीर और लद्दाख (जेकेएल) चौपटर ने जम्मू के परेड ग्राउंड स्थित गवर्नमेंट कॉलेज

अध्यक्षा श्रीमती रुचिका गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती वर्षा बंसल और सचिव श्रीमती नंदिता बजाज भी उपस्थित थीं।

यह सहयोग जीसीडब्ल्यू परेड में एक युवा महिला आत्मियता समूह (वाईडब्ल्यूएजी) की स्थापना का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र भर के प्रमुख संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही युवतियों के लिए एक समर्पित मंच तैयार करना है। वाईडब्ल्यूएजी के माध्यम से, जीसीडब्ल्यू परेड की छात्राओं को फिककी एफएलओ जेकेएल द्वारा प्रदान किए जाने वाले विविध अवसरों तक पहुँच प्राप्त होगी, जिसमें कार्यक्रमां, ज्ञान-निर्माण सत्रों, वेबिनार, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी शामिल है।

समझौता ज्ञापन के तहत, फिककी फ्लो जेकेएल कॉलेज में प्रमुख वक्ताओं को आमंत्रित करेगा ताकि वे छात्राओं से संवाद कर सकें और संस्थान के लिए निःशुल्क महिला-केंद्रित कार्यक्रम आयोजित कर सकें।

फॉर विमेन (जीसीडब्ल्यू) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जीसीडब्ल्यू परेड के प्रिंसिपल डॉ. रवेन्द्र कुमार टिक्कू और फिककी एफएलओ जेकेएल की अध्यक्षा श्रीमती आरती चौधरी ने आज इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर फिककी एफएलओ जेकेएल की पूर्व

एबीवीपी ने की सांकेतिक भूख हड़ताल, एसटी-२ छात्रवृत्ति तत्काल जारी करने की मांग

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शिक्षा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की राजौरी इकाई ने आज एसटी-२ छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी के विरोध में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी में सांकेतिक भूख हड़ताल की। इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की।

विरोध प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में लंबित एसटी-२ छात्रवृत्ति राशि का तत्काल भुगतान और छात्रवृत्ति वितरण में देरी को समाप्त करना

शामिल है। एबीवीपी ने छात्रों, विशेषकर वंचित समुदायों के छात्रों के लिए समय पर छात्रवृत्ति वितरण के महत्व पर जोर दिया। राज्य संयुक्त सचिव शमीम परवेज ने कहा, "एसटी-२ छात्रवृत्ति के वितरण में देरी की कड़ी निंदा करते हैं और लंबित राशि को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं।"

अगर सरकार शीघ्र कार्रवाई करने में विफल रहती है, तो एबीवीपी जिला और राज्य स्तर पर अपना आंदोलन तेज करेगी।

जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता और छात्र अधिकारों की रक्षा नहीं हो जाती, हम संघर्ष जारी रखेंगे।" एबीवीपी राजौरी की जिला

संयोजक रितिका शर्मा ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हमने अधिकारियों को एक कड़ा संदेश दिया है कि छात्र अब छात्रवृत्ति वितरण में देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

हम विधायक राजौरी के इस आश्वासन का स्वागत करते हैं कि एसटी-२ छात्रवृत्ति 6 सितंबर को जारी कर दी जाएगी।

हालांकि, हम सतर्क रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी अपनी प्रतिबद्धता पूरी करें। यदि छात्रवृत्ति राशि वादे के अनुसार जारी नहीं की जाती है, तो एबीवीपी छात्र अधिकारों की रक्षा के लिए अपने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को तेज करेंगे।"

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ का खतरा कम, लेकिन राजमार्ग अभी भी बंद

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू/श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में मौसम में सुधार के साथ बाढ़ का खतरा कम हो गया है, लेकिन श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी बंद है, क्योंकि भारी बारिश के कारण कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे उधमपुर और रामबन जिलों के बीच सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

जम्मू-कश्मीर यातायात पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को भी अवरुद्ध रहा, इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे मरम्मत कार्य पूरा होने और सतह के यातायात योग्य होने तक इस पर यात्रा न करें।

प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां और राजौरी के बीच मुगल रोड, किश्तवाड़-सिंथन रोड और श्रीनगर-लेह सड़कें यातायात के लिए खुली हैं। सिंथन हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के लिए खुला है, जबकि मुगल रोड और सोनमर्ग-लेह सड़कें हल्के मोटर वाहनों और भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) दोनों के लिए खुली हैं।

कश्मीर और जम्मू के बीच एकमात्र प्रमुख सड़क संपर्क मार्ग, 250 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग (एन-44), उधमपुर ज़िले में जखेनी और चेनानी के बीच कई भूस्खलनों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। यातायात पुलिस ने मंगलवार से जम्मू के नगरोंटा से रियासी, चेनानी, पटनीटॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

रामबन और उधमपुर के बीच फंसे यात्री वाहनों को राजमार्ग के भूस्खलन प्रभावित स्थानों पर अस्थायी फुटपाथों से गुजरने की अनुमति दी गई। काजीगुंड में तैनात यातायात पुलिस उपाधीक्षक मुहम्मद असलम ने बताया कि राजमार्ग बंद होने से कश्मीर से दूसरे राज्यों में फलों का परिवहन बाधित हो गया है, क्योंकि सेब और अन्य वस्तुओं से लदे 1700 से ज्यादा ट्रक काजीगुंड मार्ग पर फंसे हुए हैं।

रामबन में तैनात एक अन्य यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजमार्ग के उधमपुर खंड पर 250 ट्रक फंसे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि नाशरी सुरंग के रामबन की ओर से अब कोई भी यात्री वाहन नहीं फंसा है, क्योंकि उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है।

कश्मीर के सेब किसान संघ के अध्यक्ष जहूर अहमद भट ने कहा कि उच्च घनत्व वाले सेबों से लदे ट्रक भी राजमार्ग पर अनंतनाग जिले में काजीगुंड और खानबल के बीच फंसे हुए हैं, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रक कठुआ में फंसे हुए हैं। भट ने ईटीवी भारत को बताया, कश्मीर में फल उत्पादक और व्यापारी, जिन्होंने अपनी उच्च घनत्व वाली सेब की फसल काटी थी, चिंतित हैं क्योंकि ट्रक राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। मुगल रोड पर भी भारी ट्रकों का सुचारु संचालन अनिश्चित है। सेब की यह किस्म जल्दी खराब हो जाती है और इसका भंडारण जीवन भी स्वादिष्ट किस्म की तुलना में कम होता है।



पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	25751
छहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिममत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी छहर	25678
एसपी छहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
छहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज	2453999
सिटी ऑफिस	2573399

रेलवे

रेलवे प्लेटफॉर्म	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	24703

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थ	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्टरी पुस्तक	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
डाक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर छहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101, 132, 2476407
छहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रखौई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमीर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नाजक नगर	2430776

परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मददन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरोज़ नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चैट्टिबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चैट्टिबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

कठुआ विधायक डॉ भारत भूषण ने जंगलोट पंचायत बागड़ा में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, जरूरतमंदों को बांटा राशन



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : कठुआ विधायक दाऊ भारत भूषण अपनी टीम के साथ जंगलोट

पंचायत के बागड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की।

विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वासन दिया कि



गांव की सभी परेशानियों का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। इस मौके पर जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री और राशन भी वितरित किया गया।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख में विकास की खाई पाटने के लिए प्रतिबद्ध : उपराज्यपाल कविंदर

कहा कि लोगों की चिंताओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा



सबका जम्मू कश्मीर

कारगिल : समावेशी और जन-केंद्रित शासन के प्रति केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, लद्दाख के माननीय उपराज्यपाल, श्री कविंदर गुप्ता ने आज कहा कि सरकार विकास के अंतराल को पाटने और पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लोगों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए दृढ़ है।

कारगिल के विभिन्न क्षेत्रों से आए कई प्रतिनिधिमंडलों ने राज निवास में उपराज्यपाल से मुलाकात की और विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर अपनी माँगें और सुझाव

प्रस्तुत किए। कारगिल के उपायुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलएएचडीसी, राकेश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कारगिल, श्री राम आर. भी बैठकों के दौरान उपस्थित थे।

मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफर अखून के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कार्यकारी पार्षद आगा मुजतबा मोसावी और ट्रैस्पोन क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल थे, ने ट्रैस्पोन में एक तहसील मुख्यालय की स्थापना और वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उन्नत करने की मांग की। लद्दाख से सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने उपराज्यपाल से

मुलाकात की और कारगिल में शीतकालीन यात्रा के लिए निजी विमान सुविधा, जिला अस्पताल का विस्तार 100 से 200 बिस्तरों तक करने तथा कारगिल में एम्स और पीजीआई की तर्ज पर मल्टी-स्पेशलिटी विंग की स्थापना की मांग की।

इसी तरह, हज समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अली मजाज़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कारगिल में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना का अनुरोध किया। कारगिल से नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की और अपनी माँगें रखीं। इसी तरह, रसोइयों और सहायकों सहित संविदा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं पर प्रकाश डाला, जबकि एसकेआईएमएस में वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा कर्मचारियों के एक समूह ने अपने स्थानांतरण को लेकर चिंताएँ व्यक्त कीं।

उपराज्यपाल ने उठाए गए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन परामर्शी और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगा।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने वैष्णो देवी त्रासदी के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तीखा हमला बोला और उन्हें वैष्णो देवी त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें भूस्खलन में लगभग 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई।

चौधरी ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए संवाददाताओं से कहा, 'वैष्णो देवी में' श्राइन बोर्ड मौजूद है, जो हर चीज पर नज़र रखता है। फिर ख़राब मौसम में यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? और अगर लोग लौट भी रहे थे, तो उन्हें दरबार (मंदिर स्थल) पर क्यों नहीं रोका गया? उपराज्यपाल ने सीईओ को यात्रा रोकने का निर्देश क्यों नहीं दिया? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम संबंधी चेतावनी की अनदेखी कर तथा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर यात्रा जारी रखने की अनुमति देने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बादल फटने और भूस्खलन से पहले 26 अगस्त को दोपहर में तीर्थयात्रा स्थगित कर दी गई थी।

बोर्ड ने गुरुवार रात एक बयान में कहा, 'विशेष मौसम संबंधी चेतावनी जारी होने के बाद 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक इस मार्ग पर यात्रा स्थगित कर दी गई।' हालाँकि, बोर्ड ने इस आपदा में हुई मौतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की।

मंगलवार को कटरा क्षेत्र की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित अर्धकुंवारी में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर बादल फटने से हुए भूस्खलन में लगभग 34 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। इस दुखद घटना में 20 अन्य घायल भी हुए हैं। एलजी की अध्यक्षता वाले मंदिर बोर्ड की भूमिका की ओर इशारा करते हुए उन्होंने सवाल किया, 'क्योंकि यह बोर्ड उनके अधीन है, तो यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।' और एलजी प्रशासन पर पिछली त्रासदियों से सबक न सीखने का आरोप लगाया।

जम्मू-कश्मीर में एक ही निर्वाचित सरकार द्वारा शासन का आह्वान करते हुए, उप-मुख्यमंत्री ने कहा, आज जम्मू-कश्मीर में दो सरकारें चल रही हैं। एक उप-राज्यपाल की सरकार है और दूसरी उमर अब्दुल्ला की सरकार है। अब्दुल्ला सरकार को जनता ने चुनकर भेजा है और वह अपना कर्तव्य निभा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस दुखद समय में जम्मू में रहने के बजाय सिन्हा चुनावी राज्य बिहार का दौरा कर रहे हैं।

इस बीच, सिन्हा ने घटना के कारणों की जाँच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। यह समिति दो हफ़्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।

भारतीय सेना बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान जारी रखा हुए है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शिक्षा हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण जम्मू, सांबा, कठुआ, पठानकोट और गुरदासपुर में बाढ़ आ गई, जिससे बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा और हमारे लोग प्रभावित हुए। तत्परता से प्रतिक्रिया करते हुए, भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन के साथ निकट समन्वय में तुरंत बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान शुरू किया। 26 अगस्त से, राइजिंग स्टार कोर के भारतीय सेना के जवानों ने बाढ़ के पानी और प्रतिकूल मौसम का सामना करते हुए सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों

द्वारा समर्थित कई बचाव स्तंभों को तैनात किया है। सेना ने सक्रिय रूप से आवश्यक उपकरणों के साथ आवश्यक संख्या में स्तंभों को नियोजित किया और बच्चों, छात्रों और अर्धसैनिक बलों के जवानों सहित लगभग 1,000 फंसे हुए कर्मियों को बचाया, साथ ही तेजी से वैकल्पिक ओएफसी लाइनें बिठाकर जम्मू और श्रीनगर के लिए महत्वपूर्ण संचार संपर्क भी बहाल किया। बचाव के साथ-साथ, प्रभावित परिवारों को आवश्यक चिकित्सा सहायता, भोजन और राहत सामग्री प्रदान की गई। बाढ़ ने जम्मू में आवाजाही के लिए जीवन रेखा, तवी पुल नंबर 4 के पूर्वी हिस्से को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर

दिया। मरम्मत में समय लगने की संभावना के कारण, टाइगर डिवीजन के इंजीनियरों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में, बह गए रास्तों और सीमित कार्यस्थल को पार करते हुए, 110 फीट लंबा बेली ब्रिज तैयार किया। पुल का निर्माण 12 घंटे से भी कम समय में पूरा हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही संभव हो गई। भारतीय सेना के प्रयास नागरिक प्रशासन और सभी एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में रहे हैं। हम उनके सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी उभरती चुनौती से निपटने के लिए सेना के अतिरिक्त संसाधन तैयार रखे गए हैं।

लखनपुर में हुई अहम बैठक, बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आकलन कर सभी को दिलाया जाएगा हक



सबका जम्मू कश्मीर

लखनपुर। बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर लखनपुर

में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण, वरिष्ठ पार्टी नेता प्रेम

डोगरा, पूर्व नगरपालिका समिति अध्यक्ष रविंदर शर्मा, पूर्व एम.सी. अध्यक्ष सुरमु दीन, पूर्व उपाध्यक्ष एम. सी. लखनपुर काका राम, पूर्व

पार्षदगण, मंडल प्रधान सुमन बाला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने शिरकत की। बैठक में जोर देकर कहा गया

कि प्रशासन को नुकसानों के आकलन में पूरा सहयोग दिया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया

जाएगा कि बाढ़ से प्रभावित एक भी पीड़ित परिवार सूची से बाहर न रह जाए और सभी को उचित मुआवजा व मदद मिल सके।

थाना हसौद में शांति समिति की बैठक संपन्न, सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील



सबका जम्मू कश्मीर

सक्ती-हसौद/छत्तीसगढ़। आगामी गणेश विसर्जन एवं मिलाद-उन-नबी पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार को, जिला सक्ती के हसौद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना

प्रभारी हसौद नरेंद्र यादव द्वारा की गई। इस बैठक में क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि, डीजे संचालक, गणेश समिति के सदस्यगण एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। थाना प्रभारी ने सभी समुदायों से अपील की कि वे त्योहारों को आपसी भाईचारे एवं शांति के साथ मनाएं तथा प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना

से बचना चाहिए और विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस या प्रशासन से संपर्क किया जाए।

बैठक में विधिक साक्षरता अभियान के अंतर्गत श्रीमती शांति कुर्रे द्वारा उपस्थितजनों को कानून संबंधी आवश्यक जानकारीयों भी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक आयोजनों, डीजे संचालन एवं जुलूसों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि कोई विधिक बाधा उत्पन्न न हो। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें सभी उपस्थितजनों ने यह संकल्प लिया कि वे दोनों पवों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने में प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे।

उक्त बैठक में प्रमुख रूप से जनपद सदस्य हसौद विजय केशी उमाशंकर बर्मन सरपंच गुडरुफला दीपक मधुकर सरपंच प्रतिनिधि धमनी वरिष्ठ पत्रकार मुस्ताक कुरैशी रवि कुमार खटर्जी प्रेम दास महंत चंद्रशेखर निराला नीरज महंत विवेक बघेल ब्रिज राम पटेल चेतन प्रसाद साहू शिवम जायसवाल हरनारायण साहू चंद्रहास निराला अमरपाल खटर्जी राजू साहू धरमलाल चंद्रा सूरज केवट पुष्पेंद्र साहू राजू केवट सहित गढ़मान्य नागरिक उपस्थित रहे

वेद शर्मा ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों के लिए कांग्रेस की आलोचना की, माफी की मांग की

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : शिक्षा जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी वेद शर्मा ने बिहार में राहुल गांधी की चल रही श्मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए अपशब्दों के लिए कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की।

मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां और व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और देश के सर्वोच्च पद के प्रति अनादर को दर्शाते हैं।

शर्मा ने कहा, छद्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी, उनकी पार्टी और गठबंधन सहयोगियों को अपने निंदनीय आचरण के लिए माफी मांगनी होगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा और कार्यों की निंदा की तथा कहा कि लो. कतात्रिक व्यवस्था में राजनीतिक नेताओं के लिए ऐसा व्यवहार अनुचित है।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने हमेशा सम्मानजनक राजनीतिक संवाद पर जोर दिया है और राष्ट्रीय नेताओं को नीचा दिखाने के प्रयासों को हल्के में नहीं लिया जाएगा।

शर्मा ने कांग्रेस से आत्मचिंतन करने और सम्य राजनीतिक सहभागिता के सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया तथा इस बात पर बल दिया कि जवाबदेही और गरिमा को सार्वजनिक राजनीतिक बातचीत का मूल आधार होना चाहिए।

शर्मा ने भारत के लोगों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में रहने वाले बिहार के मतदाताओं

से इस तरह के व्यवहार पर ध्यान देने का आह्वान किया और कहा कि प्रधानमंत्री और लो. कतात्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान राष्ट्र निर्माण का मूल आधार है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा प्रधानमंत्री को बदनाम करने या उनका अपमान करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ दृढ़ता से खड़ी रहेगी और इस तरह के कृत्य के राजनी. तिक परिणाम हो सकते हैं।

शर्मा ने राष्ट्रीय संस्थाओं की गरिमा की रक्षा करने तथा भारतीय राजनीति में जवाबदेही की संस्कृति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक बहस की पवित्रता तथा भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

हीरानगर की समस्याओं को लेकर धरम पाल कुंडल ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा से की मुलाकात



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एवं जोनल सचिव (जम्मू जोन) व हीरानगर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी धरम पाल कुंडल ने आज माननीय कैबिनेट मंत्री जनाब जावेद अहमद राणा से उनके निवास पर मुलाक. त की।

इस दौरान उन्होंने मंत्री जी को हाल ही में हुई भारी बारिश से हीरानगर क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं

और लोगों को हुए भारी नुकसान के बारे में अवगत कराया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग भी रखी। मंत्री जावेद अहमद राणा ने आश्वासन दिया कि इन सभी मुद्दा. को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वे शीघ्र ही क्षेत्र का दौरा करेंगे।

लखनपुर में सुरक्षित पेयजल को लेकर शुरू किया जागरूकता अभियान



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति विभाग कठुआ ने नगर समिति लखनपुर के सहयोग से सुरक्षित पेयजल पर जागरूकता अभियान शुरू किया है।

अभियान के तहत पूरे लखनपुर शहर में जिंगल के जरिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि पीने के

पानी को हमेशा उबालकर ही इस्तेमाल करें और उसे साफ-सुथरे तरीके से स्टोर करें। साथ ही लोगों को स्वच्छता अपनाने की अपील की जा रही है ताकि जलजनित बीमारियों से बचाव हो सके। प्रशासन ने लोग. से सतर्क रहने और इन आसान उपायों को अपनाकर अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित रखने की अपील की है।

कठुआ पुलिस का बड़ा खुलासा : पाक ड्रोन गिरोह बेनकाब, 4 तस्कर गिरफ्तार



सनी शर्मा/राज कुमार

हीरानगर/कठुआ। सीमा पार से ड्रोन के जरिये नशे की सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क का कठुआ पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना (वै) की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जुड़े 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में अफीम,

हेरोइन और नकदी भी बरामद हुई है।

कैसे हुआ खुलासा

29 जुलाई को सूचना मिली कि हीरानगर के गांव छान टांडा में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन से नशीला पैकेट गिराया गया है। पुलिस और बीएसएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई कर 447 ग्राम अफीम बरामद की। मामला दर्ज कर जांच शुरू हुई।

गिरफ्तार आरोपी जांच में पंजाब के दो युवक सुखविंदर

सिंह और अर्शदीप सिंह उर्फ राजा पकड़े गए। दोनों का काम बॉर्डर पर पैकेट उठाकर आगे सप्लाई करना था। इनके पास से 411 ग्राम हेरोइन मिली। पूछताछ में सामने आया कि यह माल कठुआ के फिरोज दीन उर्फ अल्लू को दिया जाना था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अल्लू सीधे पाकिस्तान में बैठे तस्करों से संपर्क में था। इसके बाद पुलिस ने पंजाब के तरनतारन से एक ड्रग किंगपिन को भी पकड़ा। यह

हवाला के जरिये पाकिस्तान में रकम भेज रहा था। दोनों से नकदी और हेरोइन बरामद हुई।

30 किलो से ज्यादा हेरोइन सप्लाई पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह पहले ही पंजाब और जम्मू-कश्मीर में 30 किलो से ज्यादा हेरोइन सप्लाई कर चुका है। आरोपी काफी चालाकी से काम करते थे और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बच रहे थे।

पुलिस की सख्त कार्रवाई पिछले दिनों पुलिस ने नशा तस्करों की संपत्ति भी जब्त की थी। अब ड्रोन सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर कठुआ पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिले में नशे के खिलाफ मुहिम पूरी सख्ती से जारी रहेगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि नशे के खिलाफ लड़ाई में आगे आएँ और अपराधियों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि युवाओं को इस जहर से बचाया जा सके।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया ने किया नेशनल मीडिया रजिस्टर का शुभारंभ

दिल्ली और हरियाणा प्रदेश इकाइयों का भी हुआ गठन



सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली। वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया ने पत्रकारों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को नेशनल मीडिया रजिस्टर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हरियाणा भवन सभागार में हुआ, जहां बड़ी संख्या में पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और संगठन के सदस्य शामिल हुए।

पत्रकारों के लिए अहम पहल : मुख्य अतिथि

राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने कहा कि यह रजिस्टर पत्रकारों को एक मजबूत पहचान देगा और सरकार को भी देशभर के पत्रकारों की सूची बनाने में मदद मिलेगी। इसमें पत्रकारों की जानकारी, जैसे नाम, पता और कार्यक्षेत्र एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। यह रजिस्टर 12 भाषाओं में बनाया गया है और 31 अगस्त से सभी पत्रकार इसमें अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे।

नई प्रदेश इकाइयों का गठन : इस मौके पर दिल्ली और हरियाणा प्रदेश इकाइयों का गठन भी

किया गया। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान किया, जिसमें धर्मेन्द्र भदौरिया, स्वतंत्र सिंह भुल्लर, ईश मलिक और देवेंद्र तोमर जैसे वरिष्ठ पत्रकार शामिल किए गए। हरियाणा इकाई का गठन प्रदेश प्रमारी विकास सुखीजा ने किया, जिसमें शिव कुमार शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष और हरीश चावला को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

मीडिया की भूमिका पर संगोष्ठी कार्यक्रम के दूसरे सत्र में "राष्ट्रीय विकास में मीडिया की भूमिका" विषय पर संगोष्ठी हुई। वरिष्ठ पत्रकार परमानंद पांडेय और मनोज मिश्रा ने कहा कि डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता की दिशा बदल दी है और आने वाले समय में यह और मजबूत होगी।

कार्यक्रम का समापन अंत में दिल्ली इकाई अध्यक्ष संदीप शर्मा ने सभी अतिथियों और पत्रकारों का धन्यवाद किया। नेशनल मीडिया रजिस्टर की यह पहल पत्रकारिता जगत के लिए एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है, जो मीडिया कर्मियों को एकजुट और सशक्त बनाने में मदद करेगी।

कठुआ के डीसी ने रावी नदी किनारे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने शुक्रवार को लखनपुर और आसपास के इलाकों का दौरा किया। हाल ही में आई बाढ़ और बारिश के कारण रावी नदी का बहाव बदल गया था, जिससे सरकारी इमारतों को खतरा पैदा हो गया।

डीसी ने बाढ़ नियंत्रण विभाग और एनएचएआई को ज्यादा से ज्यादा मशीनें और कर्मचारियों को लगाने के निर्देश दिए, ताकि तटबंध मजबूत किए जा सकें और बाढ़ के खतरे को टाला जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अच्छे मौसम में तेजी से काम पूरा करें और सुरक्षा का भी ध्यान रखें। इससे पहले डीसी ने बाबेरा गांव जाकर



भूस्खलन से क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को तुरंत नुकसान का आकलन करने और प्रभावित परिवारों को राहत देने के निर्देश दिए।

इसके बाद डीसी ने भेड़-ब्लोरे सड़क का निरीक्षण किया, जो बाढ़ से काफी क्षतिग्रस्त हो

चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाजाही के लिए सड़क की अस्थायी मरम्मत जल्दी की जाए। इस मौके पर एडीसी विश्वजीत सिंह, एसपी राहुल चरक, तहसीलदार विक्रम कुमार, सीएचओ कठुआ और एनएचएआई के अधिकारी भी मौजूद रहे।

शिक्षक दिवस

ज्ञान के दीपक जलाओ आज है शिक्षक दिवस
स्कूल, विद्यालय बढ़ाओ आज है शिक्षक दिवस
शिक्षकों को हार पहनाकर दो इज्जत सब इन्हें
शिक्षकों को सर झुकाओ आज है शिक्षक दिवस
शिक्षा का प्रचार जो कि झुग्गी-बस्ती में करो
शिक्षा के नारे लगाओ आज है शिक्षक दिवस
शिक्षा जीवन है ये जा के निर्धनों के घर कहो



इनके बच्चे स्कूल लाओ आज है शिक्षक दिवस
जो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा का बख्शो पाठ सब उनको भी शिक्षित बनाओ आज है शिक्षक दिवस
दर-बदर आवारा बच्चों को दो शिक्षा का सबक गीत शिक्षा का सुनाओ आज है शिक्षक दिवस
नारे, झंडे और विज्ञापन हों शिक्षा से सजे शिक्षा का जिम्मा उठाओ आज है शिक्षक दिवस
अनपढ़ों को आज से दो पुस्तकें शिक्षा भरी अनपढ़ों को सब पढ़ाओ आज है शिक्षक दिवस

अनिल पठानकोटी

सबका जम्मू कश्मीर

“पत्रकारों की आवश्यकता”

‘सबका जम्मू कश्मीर’ हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र

के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें

योग्यता:

- पत्रकारिता में अनुभव
- उत्कृष्ट लेखन और संपादन कौशल
- सोशल मीडिया धारणे में काम करने का अनुभव

अपना बायोडाटा ई.मेल करें

sabkajammukashmir@gmail.com

संपर्क नंबर :

6005134383

सबका जम्मू कश्मीर

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक सदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

कठुआ में डीसी सख्त : बारिश-बाढ़ के बाद पानी की गंदगी रोकने के लिए सभी विभागों को अलर्ट

रोहित शर्मा

कठुआ। भारी बारिश और बाढ़ के बाद लोगों के सामने गंदे पानी और बीमारियों का खतरा न खड़ा हो, इसके लिए उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने आज बड़ी बैठक बुलाई। डीसी ने साफ कहा कि पानी की शुद्धता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जल शक्ति विभाग को आदेश दिए गए कि जगह-जगह पानी की टेस्टिंग तुरंत शुरू की जाए, हैंडपंप और नलों की बार-बार सफाई हो और गाड़ियों व रेडियो से जनता को जागरूक किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग को कहा गया कि गांव-गांव लोगों को पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में चेतावनी दी जाए और साफ पानी पीने के तरीके बताए जाएं। ग्रामीण विकास विभाग को गांवों में सफाई अभियान चलाने और लोगों को साफ-सफाई की अहमियत समझाने की जिम्मेदारी दी गई।

डीसी ने स्कूल-कॉलेजों में भी पानी की जांच के डेमो करवाने और बच्चों को सुरक्षित रहने की जानकारी देने के आदेश दिए। आंगनवाड़ी केंद्रों



पर भी पानी की टेस्टिंग होगी और खास सफाई अभियान चलाए जाएंगे। डीसी ने साफ कहा कि बाढ़ और भूस्खलन वाले इलाकों में लगातार पानी की टेस्टिंग हो और रिपोर्टें सार्वजनिक की जाएं ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने

कहा कि सभी विभाग तुरंत काम शुरू करें, तभी पानी से होने वाले खतरों पर काबू पाया जा सकेगा। बैठक में एडीसी, एडीसी कठुआ, सीप. ीओ, एसीडी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

छोटा विज्ञापन बड़ा फायदा क्लासीफाईड

आवश्यकता प्रॉपर्टी लोन व्यापार ज्योतिष

बुकिंग के लिए संपर्क करें

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

K2 LADIES GYM & K2 LIBRARY

GET IN SHAPE START TODAY

Workout join our gym

CONTACT NO.95418471

AIRWAN ROAD NAGRI PAROLE KATHUA

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY
AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

A WORK OF ART

A FEAT OF ENGINEERING

PROFILE 20 YEARS WARRANTY
ACCESSORIES 10 YEARS WARRANTY

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY
AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

Address: Sherpur, Kathua (J&K) | M.: 9086038088, 9419162407
Email: jmbupvc@gmail.com